www.sanjanabharati.com

दिल्ली और गौतम बुद्ध नगर से प्रकाशित। हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड व उत्तराखंड में प्रसारित

facebook.com/Sanjanabharati

राष्ट्रीय हिन्दी दैनिक

संजना भारती

RNI No. : DELHIN/2016/70240

आपका भरोसा, हमारी ताकत

2 वेनेजुएला संकट : अमेरिकी निरंकुशता और...

3 मुख्यमंत्री ने एआई आधारित हरियाणा बजट...

4 कैजुअल हो या फॉर्मल लुक विंटर सीजन में...

वर्ष: 10 | अंक: 75 | दिल्ली, बुधवार, 7 जनवरी 2026 | पृष्ठ संख्या: 4 | मूल्य: 1 रुपया

संक्षिप्त समाचार

'दो हफ्ते में दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण के कारण बताएं'

नई दिल्ली (एजेन्सी)। सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली में बिगड़ती वायु गुणवत्ता पर गंभीर चिंता व्यक्त की और वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग को समाधान सुझाने से पहले बिगड़ते वायु गुणवत्ता सूचकांक के प्रमुख कारणों की तत्काल पहचान करने का निर्देश दिया। राष्ट्रीय राजधानी में वायु प्रदूषण से संबंधित कई याचिकाओं की सुनवाई करते हुए, भारत के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने स्पष्ट किया कि स्पष्ट निदान के बिना, उपचारात्मक उपाय अप्रभावी रहेंगे। सर्वोच्च न्यायालय ने सीएक्यूएम को संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों की सूची तैयार करने और दो सप्ताह के भीतर एक बैठक आयोजित करने का निर्देश दिया, ताकि सर्वसम्मति से दिल्ली के वायु प्रदूषण के प्रमुख कारणों का निर्धारण किया जा सके। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि सीएक्यूएम का यह कर्तव्य है कि वह विभिन्न संबंधित क्षेत्रों के विशेषज्ञों को एक मंच पर लाकर व्यापक और आंकड़ों पर आधारित मूल्यांकन करे।

प्रियंका गांधी को मिली कांग्रेस की नई जिम्मेदारी

नई दिल्ली (एजेन्सी)। कांग्रेस नेतृत्व का मानना है कि असम में एक निष्क्रिय आंतरिक नेटवर्क, जिसे पार्टी संभावित स्लीपर सेल कहती है, अभी भी सक्रिय है और संगठनात्मक निर्णयों को प्रभावित कर रहा है। वरिष्ठ नेताओं के अनुसार, मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा, जो कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) में शामिल हुए, राज्य में कांग्रेस ढांचे के भीतर कुछ व्यक्तियों पर अपना प्रभाव बनाए हुए हैं। पार्टी को अब उम्मीद है कि प्रियंका गांधी वाड्रा की अधिक सक्रिय भागीदारी इस प्रभाव को बेअसर करने में सहायक होगी। पिछले असम विधानसभा चुनावों के दौरान प्रियंका गांधी वाड्रा पर्दे के पीछे काफी सक्रिय रहीं, हालांकि चुनाव प्रचार के दौरान वह सार्वजनिक रूप से नजर नहीं आईं। उस समय भूपेश बघेल राज्य के वरिष्ठ पर्यवेक्षक के रूप में कार्यरत थे। कांग्रेस के अंदरूनी सूत्रों का मानना है कि प्रियंका का सशक्त नेतृत्व, रणनीतिक स्पष्टता और कार्यकर्ताओं से जुड़ने की क्षमता संगठन को नई ऊर्जा प्रदान करने और शर्मा के जाने के बाद बचे किसी भी अप्रत्यक्ष प्रभाव का मुकाबला करने में सहायक हो सकती है।

कुपोषण के खिलाफ लड़ाई बने सामूहिक राष्ट्रीय आंदोलनः पीयूष गोयल

कुपोषण को स्थायी रूप से हटाने के लिए मूल कारण का पता लगाना और नवाचार जरूरी: पीयूष गोयल

संजना भारती/पीआईबी

नई दिल्ली। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने इस बात पर जोर दिया कि कुपोषण के खिलाफ लड़ाई को एक सामूहिक राष्ट्रीय जिम्मेदारी के रूप में आगे बढ़ाना होगा, जिसमें सरकार, निगम, समुदाय और व्यक्ति सभी समान रूप से शामिल हों। नई दिल्ली में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की ओर से आयोजित पोषण पर सीएसआर सम्मेलन को संबोधित करते हुए श्री गोयल ने कहा कि कुपोषण का उन्मूलन विकसित भारत के निर्माण और देश के दीर्घकालिक सामाजिक तथा आर्थिक भविष्य को सुरक्षित करने के लिए जरूरी है।

श्री गोयल ने कहा कि कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) व्यापार को सामाजिक प्रभाव से जोड़ने का एक अनूठा अवसर प्रदान करता है, विशेष रूप से कुपोषण के उन्मूलन में। उन्होंने बताया कि कानून कंपनियों को अपने शुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत सीएसआर गतिविधियों पर खर्च करना अनिवार्य करता है, लेकिन इसे न्यूनतम सीमा के रूप में देखा जाना चाहिए, न कि अंतिम सीमा के रूप में। उन्होंने सीएसआर को कंपनियों के लिए बोझ नहीं, बल्कि समाज में सार्थक योगदान देने का एक मूल्यवान अवसर बताया।

श्री गोयल ने जोर देते हुए कहा कि सेवा भावना देश के इतिहास, संस्कृति और परंपराओं में गहराई से समाई हुई है। उन्होंने कहा कि कई व्यक्ति और संगठन स्वेच्छा से अपने मुनाफे का एक हिस्सा सामाजिक कार्यों में लगाते हैं, जो कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) की अनिवार्य आवश्यकता से कहीं अधिक है। उन्होंने कहा कि यह सीएसआर सम्मेलन सभी हितधारकों के लिए कुपोषण के खिलाफ प्रयासों को तेज करने का एक आह्वान है।

सहकारिता राज्य मंत्री श्री कृष्ण पाल गुर्जर ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि सीएसआर सामाजिक परिवर्तन का एक शक्तिशाली साधन बनकर उभरा है, जो परोपकार से आगे बढ़कर रणनीतिक सामाजिक निवेश का एक माध्यम बन गया है। उन्होंने कहा कि शिशु संजीवनी जैसे कार्यक्रम यह दर्शाते हैं कि सहकारी ढांचा स्थानीय भागीदारी, पारदर्शिता और प्रभाव सुनिश्चित करके सीएसआर संसाधनों को ठोस सामाजिक परिणामों में कैसे प्रभावी ढंग से परिवर्तित कर सकता है। एनडीडीबी की गिफ्ट मिल्क और शिशु संजीवनी जैसी पहलों की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि ये पहल आकांक्षी जिलों, आदिवासी क्षेत्रों, आंगनवाड़ी केंद्रों और सरकारी स्कूलों को ध्यान में रखकर बनाए गए हैं, जो स्थानीय जरूरतों के अनुरूप हैं और अंतिम व्यक्ति तक सेवाएं पहुंचाते हैं। केंद्रीय मंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सीएसआर के माध्यम से एनडीडीबी फाउंडेशन फॉर न्यूट्रिशन जैसे संस्थागत मंचों का समर्थन करना केवल एक वैधानिक आवश्यकता नहीं है, बल्कि "सबका साथ, सबका विकास" की भावना के अनुरूप समावेशी विकास और राष्ट्र निर्माण में एक सक्रिय योगदान है।

सहयोगात्मक कार्रवाई के इस दृष्टिकोण को आगे बढ़ाते हुए, श्री पीयूष गोयल ने कहा कि कुपोषण एक जटिल चुनौती है जिसके उन्मूलन के लिए समन्वित कार्रवाई की जरूरत है। श्री गोयल ने जोर देते हुए कहा कि यह कार्यक्रम अंतर-मंत्रालयी समन्वय का एक सशक्त उदाहरण है, जिसमें वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, पशुपालन और मत्स्य विभाग, सहकारिता मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय और महिला एवं बाल विकास मंत्रालय प्रधानमंत्री के "समग्र सरकारी दृष्टिकोण" के विजन के अनुरूप मिलकर काम कर रहे हैं।

ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा विकसित भारत-जी राम जी कानूनः सीएम योगी

संजना भारती संवाददाता

लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को विकसित भारत-जी राम जी कानून, 2025 कानून की खूबियां बताते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में ग्रामीण भारत के कायाकल्प की दिशा में यह ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी इन्फ्रास्ट्रक्चर और रोजगार सृजन को मजबूत करने के उद्देश्य से विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एवं आजीविका मिशन (ग्रामीण) अधिनियम, 2025 पारित किया गया है, जो देश के ग्रामीण विकास के लिए मील का पत्थर साबित होगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को इस कानून से सर्वाधिक लाभ होगा। रोजगार की नई गारंटी के साथ इसे प्रदेश में लागू किया जाएगा।

यूपी को इससे सर्वाधिक लाभ, रोजगार की नई गारंटी के साथ प्रदेश में लागू करेंगेः मुख्यमंत्री

लोकभवन में पत्रकारों से वार्ता करते हुए योगी ने कहा कि जिन लोगों ने लंबे समय तक देश के संसाधनों पर डकैती डाली, गरीबों को भूख और युवाओं को बेरोजगारी व पलायन के लिए मजबूर किया, वे आज पारदर्शी सुधारों का समर्थन करने से इसलिए बच रहे हैं, क्योंकि तब जनता उनसे सवाल करेगी कि जब उन्हें मौका मिला था, तब उन्होंने यह काम क्यों नहीं किया। कांग्रेस और उसका इंडी गठबंधन इस महत्वपूर्ण अधिनियम पर सवाल खड़े कर रहा है, जबकि देशहित, श्रमिकों, किसानों और गांवों के विकास के लिए उठाए गए इस कदम का स्वागत होना चाहिए था। प्रधानमंत्री और एनडीए के प्रति आभार जताने के बजाय वे अपने पुराने, भ्रष्टाचार-प्रेरित मॉडल का बचाव कर रहे हैं। सीएम योगी ने बताया कि वीबी-जी राम जी एक्ट, 2025 की मूल भावना पारदर्शी प्रक्रिया, रोजगार की अधिकतम गारंटी और ग्रामीण क्षेत्रों में स्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण पर आधारित है। यही अधिनियम विकसित भारत-2047 के विजन की मजबूत आधारशिला बनेगा। उन्होंने कहा कि विकसित भारत का लक्ष्य तभी साकार होगा जब राज्य विकसित होंगे और राज्य तभी विकसित होंगे जब गांव विकसित होंगे। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त कर किसान आत्मनिर्भर बनेगा, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और सम्मान मिलेगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह कानून इसलिए जरूरी था क्योंकि मनरेगा के दौरान अधूरी व अस्थायी परिसंपत्तियां बनीं, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी और भुगतान में कटौती जैसी शिकायतें हर जनपद से सामने आईं। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय मनरेगा में घोटाला हुआ था जिसकी सीबीआई जाँच चली। कमजोर सोशल ऑडिट, शिकायत निवारण की खामियां, प्रशासनिक अक्षमताएं और मजदूरी में देरी लगातार बनी रहीं। खेती के मौसम में किसानों को मजदूर नहीं मिलते थे और श्रमिकों को समय पर काम व भुगतान की गारंटी नहीं मिल पाती थी।

विकसित भारत-2047 का ग्रोथ इंजन बनेगा हरियाणा-मुख्यमंत्री

छः स्तम्भ पर फोकस रखते हुए नवाचार पद्धति से पारित होगा हरियाणा का वित्त बजट-नायब सिंह सैनी

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि हरियाणा विकसित भारत-2047 का ग्रोथ इंजन साबित होगा। हरियाणा का योगदान देश हित में उपयोगी रहे, इसके लिए योजनाबद्ध तरीके से कार्य किया जा रहा है। व्यापक परामर्श, गहन अध्ययन व विशेषज्ञों की सहभागिता से हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट-2047 बनाया है।

मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी मंगलवार को गुरुग्राम यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम में हरियाणा विजन-2047 के मद्देनजर आयोजित बजट पूर्व कार्यशाला में अपने विचार रख रहे थे।

मुख्यमंत्री ने हरियाणा विजन 2047 रोडमैप के ध्येय के साथ वित्त वर्ष 2026-27 के लिए इंडस्ट्री, हेल्थ, आईटी तथा एजुकेशन सेक्टर से संबंधित हितधारकों के साथ आयोजित बजट पूर्व परामर्श बैठक (प्री बजट कंसल्टेशन) में हर पहलू पर विस्तार से चर्चा की। बैठक में उद्योग जगत एवं मैन्यूफैक्चरिंग इकाइयों से जुड़े विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों ने आगामी बजट के लिए अपने सुझाव रखे। बैठक में प्रदेश के उद्योग एवं वाणिज्य, पर्यावरण, वन एवं वन्य जीव मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विगत 11 साल में बड़ा विकासात्मक परिवर्तन नजर आया है। सकारात्मक बदलाव के साथ सर्वांगीण विकास की दिशा में सरकार कदम बढ़ा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार ने डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर का गठन किया है जो उभरते हुए वैश्विक परिवर्तन में कारगर रहेगा। ज्ञान व दूरदृष्टि सोच के साथ इस प्रकार की कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागीय योजनाओं को स्पष्ट विजन से जोड़ना होगा और गतिविधियों से अधिक परिणाम पर ध्यान देना होगा। नागरिकों के जीवन में सार्थक सुधार लाना हरियाणा सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि इसी सार्थक सोच के परिणामस्वरूप हरियाणा सरकार छः स्तम्भों पर केंद्रित हो विकसित भारत 2047 के सपने को साकार करने में सहभागिता निभाएगी। उन्होंने बताया कि हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट-2047 को छः रणनीतिक थीम पर आधारित कर तैयार किया गया है। इनमें वित्त एवं सुरक्षा, शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार क्षमता, स्वास्थ्य एवं पोषण, कृषि, खाद्य सुरक्षा एवं पर्यावरण संरक्षण, बुनियादी ढांचा विकास तथा क्षेत्रीय विकास एवं स्थानीय स्वशासन पर आधारित परियोजना को मूर्त रूप दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि वित्त वर्ष 2026-27 का बजट भी इन सभी थीमों के साथ पूरी तरह सामंजस्यपूर्ण रहेगा।

हरियाणा विजन 2047 रोडमैप के अंतर्गत आयोजित प्री-बजट मंथन कार्यशाला में राज्य को वर्ष 2047 तक विकसित, समावेशी एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में विभिन्न थीम स्पॉटलाइट्स पर गहन विचार-विमर्श किया गया। कार्यक्रम में स्वास्थ्य एवं पोषण से संबंधित प्रस्तुति हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल द्वारा दी गई। शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार योग्यता विषय पर उच्चतर एवं स्कूल शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विनीत गर्ग ने अपने विचार रखे। इसके साथ ही क्षेत्रीय विकास एवं स्थानीय स्वशासन विषय पर ऊर्जा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव ए.के. सिंह ने जानकारी दी।

वहीं कृषि, सहायक क्षेत्र, खाद्य एवं पर्यावरण विषय पर कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के प्रमुख सचिव पंकज अग्रवाल ने प्रस्तुति दी। वित्त एवं सुरक्षा विषय पर वित्त विभाग के आयुक्त एवं सचिव मोहम्मद शाइन ने प्रस्तुतिकरण देकर बारीकियों से अवगत कराया।

अवसंरचना विकास विषय पर उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. अमित कुमार अग्रवाल ने राज्य के औद्योगिक एवं आधारभूत ढांचे के विकास से जुड़े पहलुओं को विस्तार से रखा। इसी क्रम में विकास एवं पंचायत विभाग के आयुक्त एवं सचिव डॉ. साकेत कुमार द्वारा संयुक्त रूप से प्रस्तुति दी गई।

बजट पूर्व कार्यशाला में नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद्र, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, गृह विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. सुमिता मिश्रा, मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव अरुण कुमार गुप्ता, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ राज नेहरू, जीएमडीए के मुख्य सलाहकार डी.एस ढेसी, गुरुग्राम विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉ संजय कौशिक, उपायुक्त अजय कुमार सहित अन्य गणमान्य अधिकारीगण उपस्थित रहे।

दस महीनों में हर क्षेत्र में हुए विकास से विपक्ष में बौखलाहटः रविन्द्र इन्द्राज

संजना भारती संवाददाता

नई दिल्ली। दिल्ली सरकार के समाज कल्याण मंत्री रविन्द्र इन्द्राज सिंह ने मंगलवार को दिल्ली विधानसभा में उप राज्यपाल वी के सक्सेना के अभिभाषण पर सरकार की ओर से धन्यवाद प्रस्ताव रखा। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि यशस्वी प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में विकसित दिल्ली और अन्त्योदय की दिशा में कई ऐतिहासिक पहलें हुई हैं। उन्होंने कहा कि दस माह में हर क्षेत्र में हुए विकास और बड़ी योजनाओं व व्यापक सुधारों से विपक्ष में बौखलाहट है, इसलिए सदन को सुचारू रूप से चलाने में बार-बार बाधा उत्पन्न की जा रही है।

पं. दीन दयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी, बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना साकार कर रही दिल्ली सरकार, ग्रामोदय-अन्त्योदय-सर्वोदय पर जोर

समाज कल्याण मंत्री ने सरकार की उपलब्धियों को सदन में रखने और उचित मार्गदर्शन के लिए उप राज्यपाल वी के सक्सेना का आभार जताया। समाज कल्याण मंत्री ने कहा कि शिक्षा, आधारभूत संरचना, स्वास्थ्य, महिला कल्याण, जलापूर्ति, बिजली, सड़कें, औद्योगिक विकास, पर्यावरण और सामाजिक न्याय जैसे क्षेत्रों में सरकार ने विकास के नये आयाम स्थापित किये हैं।

रविन्द्र इन्द्राज ने कहा कि दिल्ली सरकार पं. दीन दयाल उपाध्याय, महात्मा गांधी और बाबा साहेब अम्बेडकर का सपना साकार कर रही है। ग्रामोदय-अन्त्योदय-सर्वोदय पर जोर दिया जा रहा है। साथ ही जनभावनाओं एवं सांस्कृतिक उत्थान की दिशा में भव्य आयोजन हुए हैं। समाज कल्याण मंत्री ने विधानसभा में अपनी बात रखने के लिए अवसर देने हेतु विधानसभा अध्यक्ष विजेंदर गुप्ता का आभार जताया।

श्रद्धा, मनोरंजन व रोजगार का संगम है गोरखनाथ मंदिर का खिचड़ी मेला

मकर संक्रांति से शुरू होकर माहभर से अधिक चलने वाले मेले की तैयारियां पूरी

संजना भारती/विज्ञप्ति द्वारा

गोरखपुर। मकर संक्रांति पर गोरखनाथ मंदिर में लगने और इससे पखवारा पूर्व शुरू होकर माह भर से अधिक समय तक चलने वाला खिचड़ी मेला श्रद्धा, मनोरंजन और रोजगार का संगम है। पूरी प्रकृति को ऊर्जस्वित करने वाले सूर्यदेव के उत्तरायण होने पर महायोगी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की अनूठी परंपरा पूरी तरह लोक को समर्पित है। गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी के रूप में चढ़ाए जाने वाला अन्न वर्षभर जरूरतमंदों में वितरित किया जाता है। मंदिर के अन्न क्षेत्र में कभी भी कोई जरूरतमंद पहुंचा, खाली हाथ नहीं लौटा। ठीक वैसे ही, जैसे बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाकर मन्नत मांगने वाला कभी निराश नहीं होता। मंदिर में खिचड़ी का यह पर्व इस वर्ष 15 जनवरी को मनेगा।

गोरखनाथ मंदिर में खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा त्रेतायुगीन मानी जाती है। मान्यता है कि तत्समय आदियोगी गुरु गोरखनाथ एक बार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में स्थित मां ज्वाला देवी के दरबार मे पहुंचे। मां ने उनके भोजन का प्रबंध किया। कई प्रकार के व्यंजन देख बाबा ने कहा कि वह तो योगी हैं और भिक्षा में प्राप्त चीजों को ही भोजन रूप में ग्रहण करते हैं। उन्होंने मां ज्वाला देवी से पानी गर्म करने का अनुरोध किया और स्वयं भिक्षाटन को निकल गए। भिक्षा मांगते हुए वह गोरखपुर आ पहुंचे और राप्ती और रोहिन के तट पर जंगलों में बसे इस स्थान पर धूनी रमाकर साधनालीन हो गए। उनका तेज देख लोग उनके खप्पर में अन्न (चावल, दाल) दान करते रहे।

त्रेतायुगीन है महायोगी गुरु गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने की परंपरा

मकर संक्रांति का पर्व आने पर यह परंपरा खिचड़ी पर्व के रूप में परिवर्तित हो गई। तब से बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाने का क्रम हर मकर संक्रांति पर अहर्निश जारी है। कहा जाता है कि उधर ज्वाला देवी के दरबार मे बाबा की खिचड़ी पकाने के लिए आज भी पानी उबल रहा है। मकर संक्रांति के पावन पर्व पर गोरक्षपीठाधीश्वर नाथ पंथ की विशिष्ट परंपरानुसार गुरु गोरखनाथ को लोक आस्था की खिचड़ी चढ़ाकर समूचे जनमानस की सुख समृद्धि की मंगलकामना करते हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार तथा देश के विभिन्न भागों के साथ-साथ पड़ोसी राष्ट्र नेपाल से भी लाखों की तादाद में श्रद्धालु शिवावतारी बाबा गोरखनाथ को खिचड़ी चढ़ाते हैं। मकर संक्रांति के दिन भोर में सबसे पहले गोरक्षपीठ की तरफ से पीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ खिचड़ी चढ़ाकर बाबा को भोग अर्पित करते हैं। तत्पश्चात नेपाल राजपरिवार की ओर से आई खिचड़ी बाबा को चढ़ाई जाती है। इसके बाद मंदिर के कपाट खोल दिए जाते हैं और जनसामान्य की आस्था खिचड़ी के रूप में निवेदित होनी शुरू हो जाती है। खिचड़ी महापर्व को लेकर मंदिर व मेला परिसर सज धजकर तैयार है। प्रशासन के साथ ही मंदिर प्रबंधन की तरफ से श्रद्धालुओं के ठहरने और अन्य सुविधाओं का पूरा इंतजाम किया गया है। गोरक्षपीठाधीश्वर एवं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ खुद भी अब तक तीन बार खिचड़ी मेला की तैयारियों की समीक्षा कर चुके हैं।

गोरखनाथ मंदिर सामाजिक समरसता का ऐसा केंद्र है जहां जाति, पंथ, महजब की बेड़ियां टूटती नजर आती हैं। इसके परिसर में क्या हिंदू, क्या मुसलमान, सबकी दुकानें हैं। यानी बिना भेदभाव सबकी रोजी रोटी का इंतजाम है। यही नहीं, मंदिर परिसर में लगने वाला खिचड़ी मेला भी जाति-धर्म के बंटवारे से इतर हजारों लोगों की आजीविका का माध्यम बनता है। मंदिर परिसर में नियमित रोजगार करने वालों से लेकर मेला में दुकान लगाने वालों तक, बड़ी भागीदारी अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों की होती है। उन्होंने कभी कोई भेदभाव महसूस नहीं किया बल्कि अपनेपन के भाव से विभोर होते रहते हैं। मेले में खरीदारी से लेकर मनोरंजन के साधनों तक का भरपूर इंतजाम हैं।

पंजाब में खेल संस्कृति को प्रफुल्लित करने के लिए जल्द तैयार होंगे 3100 खेल मैदानः हरजोत सिंह बैंस

संजना भारती संवाददाता

चंडीगढ़/लुधियाना। पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस द्वारा लुधियाना के गुरु नानक स्टेडियम में 69वीं नेशनल स्कूल खेलों का औपचारिक उद्घाटन किया गया। 16 जनवरी तक चलने वाली इन खेलों में केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय और विद्या भारती स्कूलों सहित सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों तथा अन्य शिक्षा संस्थाओं के खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं।

शिक्षा मंत्री बैंस ने कहा कि इन खेलों के दौरान जूडो अंडर-14 (लड़के एवं लड़कियां), ताइक्वांडो अंडर-14 (लड़कियां) तथा गतका अंडर-19 (लड़के एवं लड़कियां) के रोमांचक मुकाबले होंगे। उन्होंने बताया कि ये खेल मुकाबले स्थानीय बी.सी.एम. आर्या मॉडल सीनियर सेकंडरी स्कूल, शास्त्री नगर, सरकारी सीनियर सेकंडरी स्कूल पी.ए.यू., लुधियाना तथा ओपन एयर थिएटर पी.ए.यू., लुधियाना सहित विभिन्न स्थानों पर करवाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि पंजाब के साथ लुधियाना शहर के लिए भी यह बड़ी गौरव की बात है जहां 69वीं नेशनल खेलों के आयोजन का अवसर मिला है जिसमें पूरे पंजाब, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, आंध्र प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट से 1000 से अधिक खिलाड़ी तथा 350 से अधिक कोच पहुंचे हैं। उन्होंने बताया कि ठंड होने के बावजूद प्रशासन द्वारा पहले से ही पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित किए गए हैं जिनमें खिलाड़ियों के लिए आवास, भोजन, परिवहन, सुरक्षा के लिए पी.सी.आर. टीमें तैनात करना, खेल मैदानों में सी.सी.टी.वी. कैमरे लगाना आदि शामिल हैं।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि प्रदेश में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली पंजाब सरकार खेल आधारभूत संरचना के विस्तार के लिए निरंतर प्रयासरत है जिसके तहत विभिन्न गांवों एवं शहरों में 3100 खेल मैदानों का निर्माण कार्य युद्ध स्तर पर चल रहा है, अर्थात आने वाले समय में पंजाब के हर गांव में खेल स्टेडियम होगा।

पंजाब की खेल नीति से मिल रहे सकारात्मक परिणामः बैंस

प्रदेश को खेलों में अग्रणी बनाने के लिए, उन्होंने आगे बताया कि खेल नर्सरियों में बड़े स्तर पर बॉक्सिंग, हॉकी, कबड्डी तथा अन्य विभिन्न खेलों के लिए कोचों की भर्ती की जा रही है तथा खिलाड़ियों की डाइट में भी वृद्धि की गई है। उन्होंने बताया कि पंजाब सरकार द्वारा खेल नीति बनाई गई है जिसमें पहली बार ऐसा हुआ है कि जब किसी खिलाड़ी का एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ, वर्ल्ड चैंपियनशिप तथा ओलंपिक के लिए चयन होता है तो पंजाब सरकार चयनित खिलाड़ियों को एडवांस पेमेंट करेगी ताकि खिलाड़ी अपनी सुविधा अनुसार खुलकर तैयारी कर सके जबकि अन्य प्रदेशों में खिलाड़ियों को मेडल लाने के बाद ध्यान दिया जाता है।

सम्पादकीय

कार्तिगई दीपम विवाद...

मद्रास हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में तिरुप्परनकुंद्रम पहाड़ी के दीपथून पर कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति को बरकरार रखा है। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि यह परंपरा सदियों पुरानी है और इसे रोकने का कोई संवैधानिक या कानूनी आधार नहीं है। अदालत ने साथ ही राज्य सरकार द्वारा कानून व्यवस्था के नाम पर लगाए गए प्रतिबंधों को निराधार और कल्पनाजन्य करार दिया। न्यायालय ने कहा कि जिस स्थान पर दीपम जलाया जाता है वह मंदिर से जुड़ी पारंपरिक धार्मिक व्यवस्था का हिस्सा रहा है। केवल आशंका के आधार पर किसी धार्मिक परंपरा को रोका नहीं जा सकता। अदालत ने यह भी रेखांकित किया कि धार्मिक स्वतंत्रता केवल निजी पूजा तक सीमित नहीं है बल्कि सामूहिक और सार्वजनिक धार्मिक अभिव्यक्ति भी इसके अंतर्गत आती है। हम आपको बता दें कि इस मामले में राज्य सरकार ने दलील दी थी कि दीपम जलाने से सामाजिक तनाव और कानून व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। कोर्ट ने इस तर्क को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि प्रशासन का दायित्व भय पैदा करना नहीं बल्कि निष्पक्ष और साहसिक ढंग से कानून व्यवस्था बनाए रखना है। अदालत ने यह भी कहा कि यदि हर परंपरा को संभावित विवाद के नाम पर रोक दिया जाए तो संविधान में प्रदत्त धार्मिक स्वतंत्रता केवल कागज पर रह जाएगी। हम आपको बता दें कि याचिकाकर्ताओं की ओर से यह तर्क रखा गया था कि कार्तिगई दीपम केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान का प्रतीक है। इसे रोकने का प्रयास समाज में अनावश्यक विभाजन और असंतोष को जन्म देता है। कोर्ट ने इस तर्क से सहमति जताई और आदेश दिया कि परंपरागत रीति से दीपम जलाने की अनुमति दी जाए। देखा जाये तो मद्रास हाईकोर्ट का यह निर्णय उस मानसिकता पर करारा प्रहार है जो हर हिंदू परंपरा को कानून व्यवस्था के नाम पर कटघरे में खड़ा करने की आदी हो चुकी है। आज सवाल यह नहीं है कि दीपम जलेगा या नहीं। सवाल यह है कि क्या बहुसंख्यक समाज की सांस्कृतिक अभिव्यक्ति को हर बार डर और शक के चश्मे से देखा जाएगा? तमिलनाडु की द्रमुक सरकार का तर्क कि दीपम जलाने से अशांति फैल सकती है, दरअसल प्रशासनिक असफलता को छिपाने का तरीका है। अगर हर धार्मिक आयोजन से पहले सरकार को डर लगने लगे तो फिर शासन चलाने का नैतिक अधिकार किस बात का रह जाता है? अदालत ने ठीक ही कहा कि कल्पित भय के आधार पर मौलिक अधिकारों को कुचला नहीं जा सकता। देखा जाये तो यह मामला उस व्यापक प्रवृत्ति का हिस्सा है जहां हिंदू धार्मिक परंपराओं को बार बार रोकने और सीमित करने का प्रयास किया जाता है। कभी शोर का बहाना बनाया जाता है, कभी पर्यावरण का तो कभी कानून व्यवस्था का। लेकिन आश्चर्यजनक रूप से यही तर्क अन्य समुदायों के मामलों में अचानक गायब हो जाते हैं। यह दोहरा मापदंड समाज में असंतोष और अविश्वास को जन्म देता है। कार्तिगई दीपम का सामाजिक महत्व केवल आस्था तक सीमित नहीं है। यह पर्व सामूहिकता का प्रतीक है। पहाड़ी पर जलता दीप दूर दूर तक दिखाई देता है और समाज को जोड़ने का काम करता है। जब ऐसी परंपराओं को रोका जाता है तो संदेश जाता है कि बहुसंख्यक समाज की भावनाएं गौण हैं। यही भावना धीरे धीरे आक्रोश में बदलती है और फिर वही आक्रोश सामाजिक तनाव का रूप ले लेता है। इस फैसले का सबसे बड़ा सामाजिक प्रभाव यह है कि लोगों का यह विश्वास और प्रबल हुआ है कि न्यायपालिका संविधान की आत्मा को समझती है। अदालत के आदेश ने यह स्पष्ट कर दिया कि धर्मनिरपेक्षता का अर्थ यह नहीं है कि राज्य केवल एक धर्म के प्रति कठोर हो जाए और बाकी के प्रति नरम। सच्ची धर्मनिरपेक्षता सभी परंपराओं के साथ समान व्यवहार की मांग करती है। यह निर्णय प्रशासन के लिए भी चेतावनी है। उसे समझना होगा कि परंपराओं को दबाने से शांति नहीं आती बल्कि असंतोष भीतर ही भीतर सुलगता रहता है। बहरहाल, अगर आज अदालत ने दीपम जलाने के अधिकार की रक्षा नहीं की होती तो कल कोई और परंपरा इसी तरह प्रतिबंधों की भेंट चढ़ जाती। वैसे यह फैसला केवल एक धार्मिक जीत नहीं है। यह सांस्कृतिक आत्मसम्मान की पुनर्स्थापना है। यह संदेश है कि डर के नाम पर अधिकार छीने नहीं जा सकते। यह आदेश यह भी संदेश देता है कि अगर समाज चुप रहा तो उसकी परंपराएं एक एक कर खत्म कर दी जाएंगी। दीप तो अब जल जायेगा लेकिन समाज की चेतना की लौ भी जलती रहनी चाहिए क्योंकि संभव है राह में रोड़े अटकाने वाले दूसरा प्रतिबंध लगाने के लिए तैयार बैठे हों।

जयंती

चंद्रशेखर वेंकट रामन

जन्म: 7 नवम्बर, 1888; मृत्यु: 21 नवम्बर, 1970, पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने वैज्ञानिक संसार में भारत को ख्याति दिलाई। प्राचीन भारत में विज्ञान की उपलब्धियाँ थीं, जैसे-शून्य और दशमलव प्रणाली की खोज, पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के बारे में तथा आयुर्वेद के फारमूले इत्यादि। मगर पूर्णरूप से विज्ञान के प्रयोगात्मक कोण में कोई विशेष प्रगति नहीं हुई थी। रामन ने उस खोये रास्ते की खोज की और नियमों का प्रतिपादन किया जिनसे स्वतंत्र भारत के विकास और प्रगति का रास्ता खुल गया। रामन ने स्वाधीन भारत में विज्ञान के अध्ययन और शोध को जो प्रोत्साहन दिया उसका अनुमान कर पाना कठिन है।

पुण्यतिथि

जीवराज मेहता

जन्म-29 अगस्त, 1887 ई., बड़ौदा, गुजरात; मृत्यु-7 नवम्बर, 1978 ई., भारत के प्रमुख चिकित्सक और देश सेवक थे। इन्हें गुजरात राज्य का प्रथम मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ था। मेहता जी अपने विद्यार्थी जीवन से ही बहुत मेधावी और प्रतिभाशाली छात्र थे। इन्होंने अपने विद्यार्थी जीवन में ही 'इण्डियन एसोसिएशन' का गठन किया था। यहीं इनका सम्पर्क राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी से हुआ और ये गाँधी जी के सहयोगी बन गये। गाँधी जी अपना हर चिकित्सीय परामर्श डॉक्टर जीवराज मेहता से ही लिया करते थे। गाँधी जी और मेहता जी का यह सम्बन्ध जीवन पर्यन्त बना रहा था।

कल मिलेंगे

काका को रात में 12 बजे एक लड़की का फोन आता है...!
काका-हेलो कौन...?
लड़की-हम तेरे बिन अब रह नहीं सकते, तेरे बिना क्या वजूद मेरा...!
काका (खुश होकर)-कौन हैं आप...?
लड़की-तुझसे जुदा अगर हो जायेंगे तो खुद से भी हो जाएंगे जुदा..!
खुशी के मारे काका की आंखों में पानी आ गया, वो बोले-तुम सच में मुझसे शादी करोगी...?
लड़की-इस गाने को अपनी कॉलर ट्यून बंनाने के लिए 8 दबाएं...!

संजना भारती दैनिक

भगवान शंकर जी के 11वें रुद्रावतार हनुमान जी (मेंहदीपुर, श्री बाला जी) के संरक्षण में संचालित किया जाता है। समाचार पत्र का यह अंक भी उन्हीं के चरणों में श्रद्धापूर्वक समर्पित है।

स्वामी, मुद्रक, प्रकाशक एवं संपादक-**संजय कुमार** द्वारा आर.डी. प्रिंटर एंड पब्लिशर्स प्राइवेट लिमिटेड, ए-41, सेक्टर-8, नोएडा, उत्तर प्रदेश से मुद्रित तथा ए-281सी, गली नं. 3, ए-ब्लॉक, अम्बिका विहार, शिव विहार, दिल्ली-110094 से प्रकाशित। इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत संपादक उत्तरदायी।

RNI No. : DELHIN/2016/70240

Phone No.: 9871221635

E-mail ID: sanjanabharati16@gmail.com

(किसी भी वाद-विवाद में न्याय क्षेत्र दिल्ली ही होगा।)

वेनेजुएला संकट: अमेरिकी निरंकुशता और वैश्विक कानूनों का हनन

-ललित गर्ग

वेनेजुएला पर अमेरिकी सैन्य कार्रवाई और राष्ट्रपति निकोलस मादुरो की गिरफ्तारी ने एक बार फिर यह प्रश्न खड़ा कर दिया है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था वास्तव में नियम-कानूनों से संचालित होती है या फिर ताकतवर राष्ट्रों की इच्छा ही वैश्विक न्याय का नया मानदंड बन चुकी है। निश्चित तौर पर वेनेजुएला पर अमेरिकी हमला महाशक्तियों की निरंकुशता को दर्शा ही रहा है, यह वैश्विक कानूनों का अतिक्रमण भी है, जो अमेरिकी दादागिरी का त्रासद एवं विडम्बनापूर्ण संकेत है, वह केवल लैटिन अमेरिका तक सीमित घटना नहीं है, बल्कि समूची दुनिया के लिये एक खतरनाक मिसाल है। अमेरिका ने जिस तरह से वेनेजुएला में सैन्य कार्रवाई करके वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार किया है, उससे जुड़े कूटनीतिक, राजनीतिक और अन्तराष्ट्रीय कानून संबंधी सवाल जो खडे. हुए ही हैं, पर अमेरिका को हस्तक्षेप का अवसर देने के लिये मादुरो की नीतियां भी चर्चा में आई हैं। वेनेजुएला पर अमेरिकी हमले की वजहें हो सकती है, लेकिन ट्रंप को यह तो सुनिश्चित करना ही होगा कि यह राष्ट्र अस्थिरता का अड्डा न बन जाये।

अमेरिका और उसके राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप स्वयं को वैश्विक शांति का मसीहा घोषित करते नहीं थकते, लेकिन उनकी नीतियां और कार्रवाइयाँ बार-बार युद्ध, हस्तक्षेप और सत्ता परिवर्तन की मानसिकता को उजागर करती हैं। यह वही अमेरिका है जो एक ओर लोकतंत्र, मानवाधिकार और संप्रभुता की दुहाई देता है, तो दूसरी ओर एक संप्रभु राष्ट्र पर आक्रमण और उसके राष्ट्रपति को गिरफ्तार करके अमेरिका ले जाना अंतर्राष्ट्रीय दादागिरी का दुर्लभ उदाहरण है। उससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण यह है कि ट्रंप ने ऐलान किया है कि सत्ता परिवर्तन होने तक वाशिंगटन इस लैटिन

> भारत का यह दृष्टिकोण न केवल व्यावहारिक है, बल्कि नैतिक रूप से भी अधिक जिम्मेदार है। युद्ध और हस्तक्षेप किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकते। इतिहास गवाह है कि इराक और अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप के बाद अमेरिका को अंततः अपमानजनक विदाई का सामना करना पड़ा, लेकिन वे देश आज भी स्थिरता और शांति से कोसों दूर हैं

अमेरिकी देश का संचालन करेगा। यह एक खतरनाक परंपरा है, जिसकी पुनरावृत्ति अमेरिकी महाद्वीप से बाहर होने की आशंका भी बलवती हो सकती है। इसमें दो राय नहीं कि निकोलस मादुरो के पतन के बाद वेनेजुएला में मिश्रित प्रतिक्रिया होगी। अंतर्राष्ट्रीय साजिशों से मादुरो को लगातार खलनायक बनाने की कोशिशों में एक वैश्विक तंत्र लगा हुआ था। इस तरह की दोहरी नीतियां केवल विडंबनापूर्ण नहीं, बल्कि वैश्विक शांति के लिये घातक है। वेनेजुएला संकट को केवल मादुरो बनाम अमेरिका के टकराव के रूप में देखना वास्तविकता को सरलीकृत करना होगा। इसमें संदेह नहीं कि मादुरो सरकार पर आर्थिक कुप्रबंधन, दमनकारी नीतियों, चुनावी अनियमितताओं और मानवाधिकार हनन जैसे गंभीर आरोप रहे हैं। लाखों वेनेजुएलावासी देश छोड़ने को मजबूर हुए, अर्थव्यवस्था चरमरा गई और जनता त्रस्त हुई। लेकिन यह भी उतना ही सत्य है कि किसी देश की आंतरिक विफलताओं को आधार बनाकर बाहरी सैन्य हस्तक्षेप को वैध ठहराना अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की आत्मा के विरुद्ध है। यदि यही मापदंड हो, तो दुनिया के अनेक देशों में बाहरी हस्तक्षेप का अंतहीन सिलसिला शुरू हो सकता है।

दरअसल, वैश्विक कूटनीति के जानकारों का मानना है कि वेनेजुएला के मामले में अमेरिका की असली चिंता न लोकतंत्र है और न ही मानवाधिकार, बल्कि वहां के विशाल तेल भंडार हैं। वेनेजुएला विश्व के सबसे बड़े तेल भंडारों में से एक पर बैठा देश है और ऊर्जा संसाधनों पर नियंत्रण की अमेरिकी भूख कोई नई बात नहीं है। इराक, लीबिया और अफगानिस्तान इसके उदाहरण हैं, जहां लोकतंत्र स्थापना के नाम पर हस्तक्षेप हुआ, लेकिन परिणामस्वरूप अस्थिरता, गृहयुद्ध और मानवीय संकट ही पैदा हुआ। ट्रंप का यह बयान कि मादुरो को पकड़ने के अभियान का खर्च वेनेजुएला के तेल राजस्व से वसूला जाएगा, इस पूरे घटनाक्रम की मंशा को बेनकाब करता है। यह कथन स्पष्ट करता है कि यह कार्रवाई न्याय या नैतिकता से नहीं, बल्कि संसाधनों पर नियंत्रण की साम्राज्यवादी सोच से प्रेरित है। किसी देश के प्राकृतिक संसाधनों पर इस तरह दावा करना उपनिवेशवादी मानसिकता का आधुनिक संस्करण है।

इस अमेरिकी कार्रवाई के भू-राजनीतिक परिणाम भी गहरे और दूरगामी होंगे। रूस और चीन ने इसे नियम-आधारित वैश्विक व्यवस्था के लिये गंभीर खतरा बताया है। मादुरो के आलोचक रहे कुछ अमेरिकी सहयोगी देश भी अब खुलकर चिंता जता रहे हैं। यह संकट वैश्विक ध्रूवीकरण को और तेज कर सकता है। विशेष रूप से चीन को इस घटनाक्रम से अपनी क्षेत्रीय महत्वाकांक्षाओं, विशेषकर ताइवान पर अमेरिकी आलोचना को कमजोर करने का अवसर मिल सकता है। यदि अमेरिका स्वयं संप्रभुता का उल्लंघन करता है, तो वह दूसरों को किस नैतिक आधार पर संयम की सलाह देगा? वेनेजुएला संकट का एक और चिंताजनक पहलू वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाला प्रभाव है। तेल उत्पादन और आपूर्ति में किसी भी प्रकार की अनिश्चितता का सीधा असर अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर पड़ता है। तेल कीमतों में उछाल पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्थाओं को झकझोर सकता है, विशेषकर विकासशील देशों को। भारत जैसे देशों के लिये यह स्थिति अत्यंत संवेदनशील है, जहां ऊर्जा आयात पर निर्भरता अधिक है। यही कारण है कि भारत ने इस घटनाक्रम पर संतुलित रुख अपनाते हुए चिंता व्यक्त की है और दोनों पक्षों से संवाद व कूटनीतिक समाधान की वकालत की है।

भारत का यह दृष्टिकोण न केवल व्यावहारिक है, बल्कि नैतिक रूप से भी अधिक जिम्मेदार है। युद्ध और हस्तक्षेप किसी भी समस्या का स्थायी समाधान नहीं हो सकते। इतिहास गवाह है कि इराक और अफगानिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप के बाद अमेरिका को अंततः अपमानजनक विदाई का सामना करना पड़ा, लेकिन वे देश आज भी स्थिरता और शांति से कोसों दूर हैं। युद्ध शुरू करना भले आसान हो, लेकिन शांति और सुशासन स्थापित करना अत्यंत कठिन होता है-यह सत्य अमेरिका बार-बार भूलता रहा है। ट्रंप प्रशासन की सबसे बड़ी विडंबना यही है कि वह स्वयं को शांति का अग्रदूत बताता है, लेकिन उसकी हर बड़ी विदेश नीति पहल टकराव और दबाव की राजनीति पर आधारित दिखती है। यह दोहरी मानसिकता न केवल अमेरिका की विश्वसनीयता को कमजोर करती है, बल्कि संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की प्रासंगिकता पर भी प्रश्नचिह्न लगाती है। यदि शक्तिशाली राष्ट्र अपने हितों के अनुसार नियम तोड़ने लगें, तो वैश्विक व्यवस्था अराजकता की ओर बढ़ेगी।

वेनेजुएला का संकट पूरी दुनिया के लिये एक चेतावनी है। यह बताता है कि आज भी शक्ति-राजनीति मानवता, शांति और कानून से ऊपर रखी जा रही है। जरूरत इस बात की है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय एकजुट होकर इस तरह के एकतरफा हस्तक्षेपों का विरोध करे और संवाद, कूटनीति तथा बहुपक्षीय समाधान को प्राथमिकता दे। किसी भी देश में सत्ता परिवर्तन का निर्णय वहां की जनता को करना चाहिए, न कि विदेशी सेनाओं को। अंततः, अमेरिका को यह समझना होगा कि किसी निरंकुश शासक को हटाना शायद सैन्य शक्ति से संभव हो जाए, लेकिन किसी देश को स्थायी शांति, स्थिरता और समृद्धि देना केवल टैंकों और बमों से नहीं हो सकता। इसके लिये धैर्य, संवेदनशीलता और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के प्रति सम्मान आवश्यक है। यदि अमेरिका वास्तव में वैश्विक शांति का पक्षधर है, तो उसे अपनी दोहरी नीति त्यागनी होगी। अन्यथा, वेनेजुएला जैसी घटनाएँ बार-बार दोहराई जाएंगी और दुनिया एक और अस्थिर, असुरक्षित भविष्य की ओर बढ़ती जाएगी।

लेखक, पत्रकार, स्तंभकार हैं।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

अमेरिका के इशारे पर न थिरकने वाले देश कीमत चुकाने के लिए तैयार रहें!

-कमलेश पांडेय

अंतर्राष्ट्रीय जगत में आर्थिक और तकनीकी दृष्टिकोण से संपन्न अमेरिका अपनी 'डीप स्टेट खलनीति' के बल पर दुनिया का दादा बन चुका है। चूंकि जी-7 के देश उसके मजबूत हाथ हैं, इसलिए ब्रिक्स देशों की औकात उससे खुलेआम उलझने की आजतक नहीं बन पाई है। आखिर पहले भारत के पास-पड़ोस में, फिर ईरान में और अब बेनेजुएला के दास्तान जो चुगली कर रही हैं, उसके वैश्विक मायने तो यही हैं। अब अगला नम्बर शायद कम्बोडिया का आएगा, जिसे ट्रंफ ने ताजा धमकी दी है।

देखा जाए तो मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के स्वप्नद्रष्टा डॉनल्ड ट्रंफ उनकी मुद्रा को चुनौती दिलवाने वाले, यदा कदा उनको आंखें दिखाने वाले रूस-चीन के मजबूत समर्थकों के एक एक कर रीढ़ तोड़ने और इसी झांसे में जांबाज भारत को धमकाकर अपने खेमे में मिलाने के लिए सधी चालें चलना शुरू कर चुके हैं। डीप स्टेट से जुड़े लोगों की मानें तो आगे अमेरिका अभी बहुत कुछ करने वाला है। इस बात का संकेत कभी न्यूयॉर्क के महापौर ममदानी और भारतीय-अमेरिकी आशा जडेजा के इशारों से चलता है। ममदानी जहां खुलेआम स्वजातीय भारतीय देशद्रोहियों के पक्ष में खत लिख रहे हैं, वहीं आशा जडेजा ने तो खुलेआम भारत को रूसी सम्बन्धों पर नसीहत दी है।

मतलब साफ है कि दुनिया भर में ब्रिक्स और रिक (रूस-भारत-चीन) देशों का हौव्वा खड़ा कर-के रूसी राष्ट्रपति ब्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कभी अलग अलग और कभी संयुक्त मंच पर अमेरिका विरोधी शेखी बघारते आये हैं, उनके ग्लोबल साउथ के सपनों पर बम्बार्डिंग शुरू हो चुकी है। यदि डीप स्टेट के समक्ष ट्रंफ ने घुटने टेके हैं तो अब उन्हें रणनीतिक बुलंदी भी मिल रही है। रूस को यूक्रेन में, भारत को पाकिस्तान-बंगलादेश से और चीन को दक्षिण चीन सागर में उलझाए रखने की जो खतरनाक

> 1954 में ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति जैकोबो आरबेंज को हटाया गया और कार्लोस कास्टिलो आर्मास को सत्ता दी गई। तीसरा, 1963 में दक्षिण वियतनाम में राष्ट्रपति न्गो दिन्ह दीम की हत्या में सहायता दी। चतुर्थ, 1973 में चिली में सल्वाडोर एलेन्डे को उखाड़ा, और ऑगस्टो पिनोशे को सत्ता सौंपी। पांचवां, 1983 में ग्रेनाडा में सैन्य आक्रमण से सरकार बदली। छठा, 1989 में पनामा में मैनुअल नोरिएगा को हटाया

अमेरिकी साजिश है, उसकी काट अभी किसी के पास नहीं है।

अभी तक एशिया, दक्षिण अमेरिका और अफ्रीका में अमेरिका को कमजोर करने की जो चालें चीन व भारत की तरफ से अलग अलग चली जा रही थीं, इनकी हवा निकालने के लिए ही अमेरिका ने अपना आक्रामक तेवर दिखा दिया है, जिसे रोकना अब किसी के बूते की बात नहीं। सच कहूं तो अमेरिका ने 19वीं शताब्दी से ही अपना विरोधी रहे कई देशों में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से सत्ता परिवर्तन करवाए हैं, जिनमें मुख्य रूप से लैटिन अमेरिका, एशिया और मध्य-पूर्व के देश शामिल हैं।

अंतरराष्ट्रीय मामलों के जानकार बताते हैं कि वाकई ये हस्तक्षेप अक्सर डीप स्टेट के इशारे पर सीआईए के माध्यम से गुप्त अभियानों, सैन्य आक्रमणों या समर्थन के जरिए हुए। इस बात को स्पष्ट करने वाले कुछ प्रमुख ऐतिहासिक उदाहरण निम्नलिखित हैं, जो अमेरिका के विरोधी देशों को अपने हद में रहने की खुली नसीहत देते हैं। चाहे अमेरिका का पुराना प्रतियोगी सोवियत संघ हो या फिर उसके अवशेष पर खड़ा रूस और उसका नया वैश्विक पार्टनर चीन, अमेरिका के नापाक इरादों में कभी मजबूत बाधक नहीं बन पाए।

मसलन, कारण चाहे जो भी हो, लेकिन इनकी अंतर्राष्ट्रीय विवशता जगजाहिर हो चुकी है। यह स्थिति जहां एकध्रुवीय विश्व की अमेरिका परिकल्पना और उसकी दादागिरी को परिपुष्ट करती है। वहीं, बहुध्रुवीय विश्व के पैरोकारों रूस, चीन और भारत आदि की नीतिगत बेचारगी की बखिया उधेड़ देती है। आइए अमेरिकी षड्यंत्र की साल दर साल मिली सफलता पर एक नजर डालते हैं। पहला, 1953 में ईरान में मोहम्मद मोसद्देघ की सरकार को अमेरिका के इशारे उखाड़ फेंका गया, और शाह को सत्ता में लाया।

दूसरा, 1954 में ग्वाटेमाला में राष्ट्रपति जैकोबो आरबेंज को हटाया गया और कार्लोस कास्टिलो आर्मास को सत्ता दी गई। तीसरा, 1963 में दक्षिण वियतनाम में राष्ट्रपति न्गो दिन्ह दीम की हत्या में सहायता दी। चतुर्थ, 1973 में चिली में सल्वाडोर एलेन्डे को उखाड़ा, और ऑगस्टो पिनोशे को सत्ता सौंपी। पांचवां, 1983 में ग्रेनाडा में सैन्य आक्रमण से सरकार बदली। छठा, 1989 में पनामा में मैनुअल नोरिएगा को हटाया। सातवां, 2003 में इराक में सद्दाम हुसैन शासन को समाप्त कर उन्हें फांसी पर लटकवाया।

आठवां, 2011में लीबिया में मुअम्मर गद्दाफी के पतन में सहयोग दिया। नवाँ, 2026 में वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को बंदी बनाया और कम्बोडिया के राष्ट्रपति को धमकाया। दरअसल, ये सूची प्रमुख मामलों तक सीमित है; जबकि कुल 80 से अधिक ज्ञात अमेरिकी हस्तक्षेप हुए हैं। हैरत की बात है कि अमेरिका के विरोधी देशों ने उसके सत्ता परिवर्तनों पर अक्सर खामोशी साधी या सीमित विरोध किया, क्योंकि सैन्य, आर्थिक और कूटनीतिक शक्तियों का असंतुलन उन्हें प्रत्यक्ष टकराव से रोकता था। सोवियत संघ जैसे प्रतिद्वंद्वी भी कई मामलों में अपनी सीमाओं के कारण सक्रिय हस्तक्षेप से परहेज करते रहे। वह सिर्फ भारत के मामले में ही कामयाब हो पाया, जहां अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं-पहला, सैन्य श्रेष्ठताः अमेरिका की परमाणु क्षमता और विशाल सेना ने विरोधियों को जोखिम लेने से रोका, जैसे चिली (1973) में सोवियत संघ ने केवल निंदा की। दूसरा, आर्थिक निर्भरताः कई देश अमेरिकी सहायता या व्यापार पर निर्भर थे, जिससे खुला विरोध अव्यवहारिक था। तीसरा, क्षेत्रीय प्रभावः लैटिन अमेरिका जैसे क्षेत्रों में अमेरिका का प्रभुत्व (मुनरो सिद्धांत) विरोध को अप्रभावी बनाता था। इसलिए सामरिक प्रतिक्रियाएं नगण्य रहीं। चतुर्थ, प्रतिसादः विरोधी देशों ने खुद गुप्त सहायता दी, जैसे क्यूबा ने अंगोला में हस्तक्षेप किया। पांचवां, कूटनीतिः संयुक्त राष्ट्र में प्रस्ताव लाए गए लेकिन वीटो के कारण विफल रहे। छठा, आंतरिक प्राथमिकताएंः चीन-रूस जैसे देशों की अपनी घरेलू चुनौतियां सक्रिय विरोध को सीमित करती रहीं।

हैरत की बात तो यह है कि अब रूस और चीन की तरह ही गुटनिरपेक्ष देश भारत को भी अमेरिकी नसीहत मिल रही है, जो गम्भीर बात है। गत दिनों जब वेनेजुएला पर अमेरिका के हमले ने दुनिया का ध्यान खींचा है तो इस घटनाक्रम पर अलग-अलग तरह के रिएक्शन दुनियाभर से सामने आ रहे हैं। इसी बीच भारतीय-अमेरिकी वेंचर कैपिटलिस्ट आशा जडेजा मोटवानी ने वेनेजुएला के घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए भारत पर तंज कसा है।

आशा ने कहा है कि वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो ने रूस से बहुत सारे हथियार खरीद रखे थे। हालांकि जब अमेरिका ने हमला किया तो ये हथियार काम नहीं आए। अमेरिकी सैनिक मादुरो तक पहुंचे और उनको बंधक बनाकर अमेरिका ले आए। ऐसे में भारत को भी इससे सतर्क हो जाना चाहिए क्योंकि भारत के पास भी ज्यादातर रूस के ही हथियार हैं।

आशा मोटवानी ने एक्स पर किए गए अपने पोस्ट में लिखा, 'वेनेजुएला के रूसी मिलिट्री इक्विपमेंट अमेरिकी मिलिट्री के सामने कुछ सेकंड में टूट गए। उम्मीद है भारत देख रहा होगा। हमारे लिए यह जानना समझदारी होगी कि हमारी रोटी का कौन सा हिस्सा मक्खन लगा हुआ है, कौन हमारे ताकतवर दोस्त हैं और कौन नहीं।' अपनी पोस्ट में आशा ने भारतीय अमेरिकियों और भारतीय रूसियों की संख्या के अंतर को बढ़ा-चढ़ाकर बताते हुए एक गलत आंकड़ा दिया- 'भारतीय अमेरिकीः 5,000,000। भारतीय रूसीः 5।'

दरअसल, भारतीय मूल की वेंचर कैपिटलिस्ट आशा जडेजा हालिया समय में अमेरिका में चर्चा में आती रही हैं। हाल ही में उन्होंने दावा किया था कि उनकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप ने H1-B पर अपना रुख बदला था। सिलिकॉन वैली की वेंचर कैपिटलिस्ट आशा डानाल्ड ट्रंप को सबसे ज्यादा दान देने वाले लोगों में शुमार हैं। आशा जडेजा मोटवानी ने 200 से ज्यादा टेक स्टार्टअप्स में निवेश किया है। उनके प्रमुख निवेशों में गूगल, पिंटरेस्ट, यूलू, क्रेडलवाइज, एडहैक टेक्नोलॉजीज, क्लिमैक्टिक और नेशनल एसोसिएशन ऑफ पेडियाट्रिक नर्स प्रैक्टीशनर्स शामिल हैं। आशा के पति राजीव मोटवानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में कंप्यूटर विज्ञान के प्रोफेसर रहे हैं। 2001 में उन्हें गोडेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

(इस लेख में लेखक के अपने विचार हैं।)

नेपाल में भी हिंदु निशाने पर! भारत से सटे बीरगंज में हालात बेकाबू

(एजेन्सी)।

बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदुओं पर अत्याचार की खबरें तो लगातार सामने आ ही रही हैं साथ ही अब नेपाल में बहुसंख्यक हिंदुओं को निशाना बनाये जाने की खबरें भी आने लगी हैं। हम आपको बता दें कि सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियोज में मुसलमानों को अपने घरों की छतों से हिंदुओं पर पत्थर बरसाते हुए देखा जा सकता है। हम आपको बता दें कि नेपाल के भारत से सटे सीमावर्ती शहर बीरगंज में इस समय हालात बेकाबू हो गये हैं। शहर के कई हिस्सों में तनाव, आगजनी और तोड़फोड़ की घटनाओं के बाद प्रशासन को कर्फ्यू लागू करना पड़ा है। हम आपको बता दें कि यह इलाका भारत नेपाल सीमा के बेहद नजदीक है, जिस कारण हालात की गंभीरता और बढ़ गयी है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, पूरे विवाद की शुरूआत एक सोशल मीडिया वीडियो से हुई, जो टिकटॉक पर तेजी से वायरल हुआ। इस वीडियो में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाली सामग्री होने का आरोप लगाया गया, जिसके बाद स्थानीय समुदायों में भारी आक्रोश फैल गया। देखते ही देखते प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आये और मामला सांप्रदायिक तनाव में बदल गया।

हम आपको बता दें कि हालात तब और बिगड़ गये जब कुछ इलाकों में धार्मिक स्थलों के साथ तोड़फोड़ की खबरें सामने आयीं। इसके बाद प्रदर्शन हिंसक हो गये। दुकानों को नुकसान पहुंचाया गया, टायर जलाये गये और मुख्य सड़कों को जाम कर दिया गया। पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़पें भी हुईं। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने बीरगंज के संवेदनशील इलाकों में कर्फ्यू लागू कर दिया। पहले यह कर्फ्यू सीमित समय के लिये लगाया गया था, लेकिन हालात सामान्य न होने के कारण इसे बढ़ाना पड़ा। प्रशासन ने साफ किया कि कर्फ्यू के दौरान अनावश्यक आवाजाही पर सख्त कार्रवाई की जायेगी।

हम आपको बता दें कि कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये बड़ी संख्या में सुरक्षाबलों को तैनात किया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि अगर हिंसा दोबारा भड़की तो और कठोर कदम उठाये जा सकते हैं। जरूरी सेवाओं को छूट दी गयी है, लेकिन आम नागरिकों से घरों में रहने की अपील की गयी है। उधर, बीरगंज की स्थिति का असर भारत नेपाल सीमा पर भी साफ दिख रहा है। सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गयी है और सुरक्षा एजेंसियां किसी भी संभावित खतरे को लेकर सतर्क हैं। दोनों देशों के अधिकारियों के बीच लगातार संपर्क बनाये रखा जा रहा है ताकि हालात नियंत्रण में रहें।

देखा जाये तो भारत नेपाल सीमा से सटे बीरगंज में भड़की हिंसा उस गहरी सामाजिक बेचैनी का नतीजा है जो पिछले कुछ वर्षों से नेपाल के भीतर लगातार पकती रही है। एक वायरल सोशल मीडिया वीडियो से शुरू हुआ विवाद, मस्जिद में तोड़फोड़, सड़कों पर उग्र प्रदर्शन और अंततः कर्फ्यू तथा सीमा सील होने तक की नौबत यह दिखाती है कि नेपाल आज किस नाजुक मोड़ पर खड़ा है। नेपाल लंबे समय तक एक घोषित हिंदू राष्ट्र रहा है। राजशाही काल में धार्मिक पहचान स्पष्ट थी, लेकिन सामाजिक संतुलन अपेक्षाकृत स्थिर था। मुसलमान, बौद्ध और अन्य समुदाय हिंदू बहुल समाज के साथ रहते आये और कभी बड़े पैमाने पर टकराव की घटना नहीं हुई। लेकिन राजशाही के अंत और धर्मनिरपेक्ष गणराज्य बनने के बाद नेपाल की पहचान एक तरह से अधर में लटक गयी। बीरगंज का मामला बताता है कि धार्मिक भावनाएं अब तर्क से नहीं, उन्माद से संचालित हो रही हैं।

सोशल मीडिया संवाद का माध्यम बनने की बजाय भीड़ को भड़काने का हथियार बन गया है। अफवाहें सत्य से ज्यादा तेज दौड़ती हैं और नफरत शांति को रौंदती चली जाती है। यह भी समझना जरूरी है कि यह आग अचानक नहीं लगी। नेपाल पिछले कुछ वर्षों से राजनीतिक अस्थिरता, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और पहचान की राजनीति से जूझ रहा है। जब शासन कमजोर होता है, जब जनता का भरोसा टूटता है, तब समाज के भीतर छिपी दरारें उभर कर हिंसा का रूप ले लेती हैं। धर्म ऐसे समय में सबसे आसान औजार बन जाता है। नेताओं के लिये भी और उकसाने वालों के लिये भी। बीरगंज में यही हुआ।

लंदन की तिजोरियां खाली, मुंबई में चांदी का राज!

(एजेन्सी)।

ग्लोबल कमोडिटी मार्केट में एक ऐसी खामोश हलचल हो रही है जिसने पश्चिमी देशों के वित्तीय गलियारों में चिंता बढ़ा दी है। सालों तक चाँदी की नब्ज लंदन और न्यूयॉर्क के हाथों में रही, लेकिन 2025 में भारत उस व्हेल की तरह उभरा है, जो अब सिर्फ खेल का केवल हिस्सा भर नहीं रहा बल्कि उसके नियम भी तय कर रहा है। कभी गरीब का सोना कहे जाने वाली चांदी ने सिर्फ 12 महीनों में करीब 180 फीसदी की जबरदस्त छलांग लगाकर उद्योग, निवेशकों और नीति-निमार्ताओं, तीनों का ध्यान खींचा है। दुनिया के दूसरे सबसे बड़े उत्पादक देश चीन द्वारा 1 जनवरी से इसके निर्यात पर लगे अनेक प्रतिबंधों के चलते माना जा रहा है कि आने वाले महीनों में भी चांदी की चमक बरकरार रहेगी। वैसे चांदी में यह बढ़त केवल हालिया नहीं है। बीते 45 सालों में इसके दामों में करीब 88 गुना तक की बढ़ोतरी हो चुकी है। भारतीय वाणिज्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों ने दुनिया को चौंका दिया है। साल 2025 के शुरूआती महीनों में ही भारत ने करीब 6,000 मीट्रिक टन चांदी का आयात किया है। यह मात्रा पूरी दुनिया में होने वाले कुल वार्षिक खनन का लगभग 25% है। विशेषज्ञों का कहना है कि यह चांदी अब लंदन की तिजोरियों से निकलकर सीधे भारतीय हाथों में आ गई है, जहाँ से इसका वापस ग्लोबल मार्केट में आना नामुमकिन है।

अब तक माना जाता था कि भारतीय खरीदार केवल कीमतें गिरने पर ही चांदी खरीदते हैं। लेकिन इस बार कहानी अलग है। भारत अब 'बाइंग द रिप' की रणनीति अपना रहा है, यानी बढ़ती कीमतों पर भी आक्रामक खरीदारी। जहां अंतरराष्ट्रीय मार्केट में चांदी की 'पेपर' कीमत कम दिख रही है, वहीं मुंबई के हाजिर बाजार में यह $75 प्रति औंस के करीब पहुंच गई है। यह इस बात का संकेत है कि भारत ने पश्चिमी देशों के 'कागजी भाव' को नकार दिया है।

एशेज में स्टीव स्मिथ का 13वां शतक, ट्रैविस हेड की ऐतिहासिक सिडनी पारी

(एजेन्सी)।

स्टीव स्मिथ ने एशेज में अपना 13वां शतक पूरा करते ही एक बड़ा रिकॉर्ड अपने नाम कर लिया। वह अब एशेज में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में दूसरे स्थान पर पहुँच गए हैं। इस सूची में उनसे आगे केवल सर डॉन ब्रैडमैन हैं, जिनके नाम 19 शतक दर्ज हैं। इससे पहले स्मिथ और जैक हॉब्स 12-12 शतकों के साथ संयुक्त रूप से दूसरे स्थान पर थे, लेकिन सिडनी में नाबाद 129 रन की पारी खेलकर स्मिथ ने यह बढ़त बना ली है। गौरतलब है कि इंग्लैंड के खिलाफ स्मिथ के अब कुल 13 शतक हो चुके हैं, जो किसी एक विपक्षी टीम के खिलाफ संयुक्त रूप से दूसरे सबसे ज्यादा हैं। इस मामले में भी ब्रैडमैन ही उनसे आगे हैं। वहीं, सुनील गावस्कर ने वेस्टइंडीज के खिलाफ और जो रूट ने भारत के खिलाफ 13-13 शतक लगाए हैं। मौजूद जानकारी के अनुसार, एशेज में स्मिथ अब तक 3682 रन बना चुके हैं और वह इस प्रतिष्ठित सीरीज के दूसरे सबसे सफल रन-स्कोरर बन गए हैं। उन्होंने सिडनी टेस्ट के दौरान जैक हॉब्स के 3636 रनों के रिकॉर्ड को पीछे छोड़ा। कुल मिलाकर इंग्लैंड के खिलाफ स्मिथ का रन-एग्रीगेट भी ब्रैडमैन के बाद दूसरा सर्वश्रेष्ठ है। यह भी उल्लेखनीय है कि सिडनी टेस्ट में यह स्मिथ का 37वां टेस्ट शतक रहा, जिससे उन्होंने राहुल द्रविड़ को पीछे छोड़ते हुए टेस्ट क्रिकेट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाजों की सूची में छठा स्थान हासिल किया है। स्मिथ ने 219 पारियों में यह मुकाम छुआ, जो रिकी पोंटिंग और कुमार संगकारा के बाद तीसरा सबसे तेज आंकड़ा है।

सिर्फ बल्लेबाजी ही नहीं, कप्तान के रूप में भी स्मिथ का रिकॉर्ड प्रभावशाली रहा है। टेस्ट क्रिकेट में कप्तान रहते हुए उनके नाम अब 18 शतक हैं और घरेलू टेस्ट में 11 शतक लगाकर वह इस मामले में रिकी पोंटिंग के बराबर पहुँच चुके हैं। सिडनी क्रिकेट ग्राउंड पर उनके नाम पांच टेस्ट शतक हैं और रन के लिहाज से वह यहाँ भी पोंटिंग के बाद दूसरे स्थान पर हैं।

दूसरी ओर, ट्रैविस हेड के लिए यह टेस्ट खास रहा है। उन्होंने सिडनी में अपना पहला टेस्ट शतक जमाया और इसके साथ ही ऑस्ट्रेलिया के उन चुनिंदा बल्लेबाजों में शामिल हो गए हैं जिन्होंने देश के सभी सात प्रमुख टेस्ट वेन्यू पर शतक लगाए हैं। इससे पहले यह उपलब्धि स्टीव वॉ, मैथ्यू हेडन, जस्टिन लैंगर और डेविड वॉर्नर के नाम रही है। गौरतलब है कि हेड के टेस्ट करियर के 12 शतकों में से सात स्कोर 150 से अधिक के रहे हैं।

मेरे पिता का नाम कभी नहीं मिटाया जा सकता-रितेश देशमुख

(एजेन्सी)। बॉलीवुड अभिनेता रितेश देशमुख ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण द्वारा उनके दिवंगत पिता एवं पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को लेकर की गई टिप्पणी पर भावुक प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए मंगलवार को कहा कि उनके पिता का नाम नहीं मिटाया जा सकता। अभिनेता ने एक वीडियो बयान में कहा, मैं हाथ जोड़कर कहना चाहता हूं जो लोग जनता के लिए जीते हैं, उनके नाम लोगों के दिल में गहरी छाप छोड़ जाते हैं। लिखे हुए को मिटाया जा सकता है, लेकिन गहरी छाप को नहीं। सोमवार को एक विवादित टिप्पणी में चव्हाण ने कहा था कि दिवंगत कांग्रेस के दिग्गज नेता विलासराव देशमुख की यादें उनके गृह नगर लातूर से मिटा दी जाएंगी। पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए चव्हाण ने कहा था, आपका उत्साह देखकर मैं सौ फीसदी भरोसे से कह सकता हूं कि विलासराव देशमुख की यादें इस शहर (लातूर) से मिट जाएंगी। इन टिप्पणियों की कांग्रेस ने कड़ी आलोचना की और भाजपा पर राज्य के विकास के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले नेता के योगदान को कमतर आंकने का आरोप लगाया। पार्टी ने कहा कि इस तरह के बयान सत्ता के अहंकार और देशमुख की विरासत के प्रति अज्ञानता को दर्शाते हैं।

मुख्यमंत्री ने एआई आधारित हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल का किया शुभारंभ

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विजन 2047 के मद्देनजर गुरुग्राम में आयोजित प्री बजट सेशन के दौरान एआई आधारित हरियाणा बजट जनभागीदारी पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के माध्यम से आम नागरिकों को राज्य के बजट निर्माण प्रक्रिया में प्रत्यक्ष रूप से सहभागी बनने का अवसर मिलेगा। पोर्टल पर हरियाणवी, हिंदी तथा अंग्रेजी तीनों भाषाओं में अपने सुझाव दिए जा सकते हैं, जिससे समाज के हर वर्ग की सहभागिता सुनिश्चित हो सके। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह प्लेटफॉर्म हमारी पारदर्शिता, नागरिक सहभागिता

तथा सहभागी शासन की प्रतिबद्धता का प्रतीक है।

इस पोर्टल के माध्यम से नागरिक, विशेषज्ञ और हितधारक सीधे सरकार से जुड़ सकेंगे। अपने व्यावहारिक सुझाव साझा कर सकेंगे और बजट निर्माण की प्रक्रिया को अधिक खुला, निरंतर और संवाद से परिपूर्ण बना सकेंगे।

इस अवसर पर हरियाणा के उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री राव नरबीर सिंह, पटौदी की विधायक बिमला चौधरी, गुरुग्राम के विधायक मुकेश शर्मा, मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर, मुख्यमंत्री के ओएसडी डॉ. राज नेहरू सहित अन्य वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे।

राजौंद में पुस्तकालय न होने से नागरिकों में रोष, वर्षों से उठ रही है लाइब्रेरी की मांग

■ युवाओं के भविष्य और नशामुक्त समाज के लिए पुस्तकालय जरूरी, कैथल मार्ग पर रैन-बसेरा के पास जगह चिन्हितः नपा सचिव नरेंद्र शर्मा

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

राजौंद। नगर राजौंद में अब तक सार्वजनिक पुस्तकालय की सुविधा न होने से नागरिकों में भारी रोष व्याप्त है। नगरवासी पिछले कई वर्षों से लाइब्रेरी निर्माण की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा इस दिशा में ठोस कदम न उठाए जाने से लोगों में नाराजगी बढ़ती जा रही है।

नगर के नागरिक प्रताप प्रजापति, नफे सिंह, सेमी लाल, रवि पुहाल, बबलू दीपक, विशाल, नरेश कुमार सहित अन्य ने बताया कि यदि नगर में पुस्तकालय की स्थापना की जाती है तो इससे युवाओं में पढ़ाई के प्रति रुचि बढ़ेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं के इस दौर में युवा सामान्य ज्ञान एवं अन्य विषयों की बेहतर तैयारी कर सकेंगे, जिससे वे नगर व अपने माता-पिता का नाम रोशन करेंगे।

नागरिकों का कहना है कि पुस्तकालय खुलने से युवा नशे जैसी सामाजिक बुराइयों से भी दूर रहेंगे और किताबों से सकारात्मक विचार ग्रहण कर अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकेंगे। उन्होंने सरकार और प्रशासन से सामाजिक सरोकार से जुड़े ऐसे कार्यों को

नपा सचिव नरेंद्र शर्मा।

भीम सिंह राणा प्रधान मार्केट यूनियन राजौंद।

प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने की मांग की। इस संबंध में नगर पालिका सचिव नरेंद्र शर्मा ने बताया कि नगर के कैथल मार्ग पर रैन-बसेरा के पास लाइब्रेरी निर्माण के लिए स्थान चिन्हित कर लिया गया है। बहुत जल्द उक्त स्थान की चारदीवारी कराकर पुस्तकालय की शुरूआत कर दी जाएगी।

मार्केट यूनियन राजौंद प्रधान भीम सिंह राणा ने कहा कि नपा सचिव पहले ही राजौंद के कैथल मार्ग पर नगर के युवाओं के लिए सुसज्जित लाईब्रेरी बनाने की घोषणा कर चुके हैं जो नगर के लिए खुशी की बात है।

पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह द्वारा निजी अस्पतालों को मुख्यमंत्री सेहत योजना में शामिल होने का न्योता

एसबी संवाददाता

चंडीगढ़। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की सोच के अनुरूप पंजाब सरकार द्वारा जल्द लागू की जाने वाली 10 लाख रुपये की नकदी रहित स्वास्थ्य बीमा पहल के विस्तार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम के तहत स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने आज प्रमुख निजी अस्पतालों को मुख्यमंत्री सेहत योजना (एम.एम.एस.वाई.) के तहत सूचीबद्ध होकर पंजाब के लोगों को व्यापक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करने संबंधी पंजाब सरकार के इस नेक प्रयास में शामिल होने का न्योता दिया।

स्वास्थ्य मंत्री, जिनके साथ प्रमुख सचिव स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कुमार राहुल तथा मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सी.ई.ओ.) राज्य स्वास्थ्य एजेंसी (एस.एच.ए.) संयम अग्रवाल भी मौजूद थे, यहां राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के कार्यालय में प्रमुख निजी अस्पतालों के प्रतिनिधियों के साथ एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे।

प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए डॉ. बलबीर सिंह ने प्रदेश के हर परिवार को मानक एवं नकदी रहित स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच प्रदान करने संबंधी पंजाब सरकार की दृढ़ प्रतिबद्धता को दोहराया। एम.एम.एस.वाई. के तहत प्रति परिवार 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य आम आदमी के कंधों से चिकित्सा उपचार के वित्तीय बोझ को दूर करना है। उन्होंने कहा कि हमारा उद्देश्य एक मजबूत स्वास्थ्य देखभाल इकोसिस्टम स्थापित करना है ताकि पंजाब का कोई भी निवासी धन की कमी के कारण उपचार से वंचित न रहे। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री सिहत योजना इस दिशा में एक क्रांतिकारी कदम है और इसकी सफलता के लिए निजी अस्पतालों की सक्रिय भागीदारी बहुत महत्वपूर्ण है। इस बात पर जोर देते हुए कि निजी अस्पताल एम.एम.एस.वाई. के सफल कार्यान्वयन में महत्वपूर्ण साझेदार हैं, स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों से मिल रहा उत्साहजनक प्रतिक्रिया पंजाब भर में इस योजना की पहुंच को और मजबूत करेगा। कैबिनेट मंत्री ने आगे कहा कि इस योजना को पारदर्शिता एवं कार्य-कुशलता के नजरिए से पूरी सोच-विचार के बाद तैयार किया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इसका लाभ जमीनी स्तर पर पंजाब के हर निवासी तक पहुंचे। उन्होंने अस्पतालों से अपील की कि वे इस योजना के तहत सूचीबद्ध होने संबंधी औपचारिक प्रक्रियाओं को तेजी से पूरा करें ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पंजाब के निवासियों को जल्द से जल्द इस योजना का लाभ मिलना शुरू हो सके।

इस बैठक में मैक्स, फोर्टिस, शाल्बी एवं लिवासा अस्पताल समेत अन्य उच्च-स्तरीय निजी स्वास्थ्य देखभाल प्रदाताओं ने पूरे उत्साह से हिस्सा लिया। इन अस्पतालों के प्रतिनिधियों ने इस योजना में शामिल होने के लिए गहरी रुचि दिखाई तथा एक सहयोगी एवं जन-केंद्रित स्वास्थ्य देखभाल मॉडल तैयार करने के लिए राज्य सरकार की सक्रिय पहल की सराहना की। इस वार्ता सत्र के दौरान स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह एवं राज्य स्वास्थ्य एजेंसी के सी.ई.ओ. संयम अग्रवाल ने इन अस्पतालों के प्रतिनिधियों द्वारा उपचार पैकेजों, सूचीबद्ध होने की प्रक्रिया एवं कैशलेस इंटरफेस के तकनीकी पहलुओं बारे उठाए गए विभिन्न सवालों के जवाब भी दिए।

पंचायती भूमि पर निर्मित रिहायशी कब्जे को नियमित करवाने के लिए 16 जनवरी तक करें आवेदनः डीसी

एसबी संवाददाता

कैथल। डीसी अपराजिता ने कहा कि जिले में गैर कृषि पंचायती भूमि पर 31 मार्च 2004 से पहले निर्मित रिहायशी कब्जे को नियमित करवाने के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 16 जनवरी 2026 तक रहेगी।

इस आवेदन को संबंधित खंड पंचायत एवं विकास अधिकारी कार्यालय में किया जा सकता है। इन आवेदनों पर सरकार की पॉलिसी के अनुसार नियमित करवाने की कार्रवाई को पूरा किया जाएगा। आवेदन की अंतिम तिथि के

उपायुक्त कैथल अपराजिता।

पश्चात प्राप्त होने वाले आवेदनों पर विचार नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी सभी खंड विकास एवं पंचायत अधिकारियों के माध्यम से सभी पंचायतों से इस कार्य को गंभीरता से करवाना सुनिश्चित करे।

इसके साथ ही सभी ग्राम पंचायतें अपने-अपने गांवों की ऐसे ग्रामीणों को सूचना देना सुनिश्चित करें ताकि पात्र व्यक्तियों को योजना का लाभ समय रहते मिल सके और पंचायत को अनावश्यक कोर्ट केसों से निजात मिल सके।

नगरीय विकास परियोजनाओं को विकसित भारत @2047 के लक्ष्य के अनुरूप किया जाए क्रियान्वितः मुख्यमंत्री डॉ. यादव

एसबी संवाददाता

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में नगरीय विकास परियोजनाओं को विकसित भारत@2047 के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए क्रियान्वित किया जाए। नगरीय निकायों की आर्थिक स्थिति को सुधारने, नगरीय क्षेत्रों में निजी निवेश को बढ़ाने, नागरिक सेवा में सूचना प्रौद्योगिकी आधारित प्रणालियों के अधिकाधिक उपयोग, अर्बन मोबिलिटी तथा ई-वाहन के उपयोग को प्रोत्साहित करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। 'नमामि गंगा अभियान' के समान ही 'नमामि नर्मदे परियोजना' पर कार्य आरंभ कर नर्मदा नदी तट की नगरीय बसाहटों के ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन, पर्यावरणीय सुधार और उपचारित जल के पुनः उपयोग के लिए कार्य योजना बनाई जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सभी नगरीय निकायों में जलापूर्ति और सीवरेज व्यवस्थाओं के प्रति विशेष रूप से सजगता और सतर्कता बरती जाए। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंगलवार को मंत्रालय में मध्यप्रदेश अर्बन डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड के संचालक मंडल की 11वीं बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में नगरीय विकास एवं आवास राज्य मंत्री श्रीमती प्रतिमा बागरी, मुख्य सचिव श्री अनुराग जैन तथा संचालक मंडल के पदाधिकारी उपस्थित थे। बैठक में कंपनी के प्रबंधकीय, वित्तीय और लेखा परीक्षा तथा अंकेक्षण संबंधी विषयों पर विचार-विमर्श कर आवश्यक निर्णय लिए गए।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में प्रदेश में शहरी विकास के लिए म.प्र. अर्बन डेवलपमेंट कंपनी में 4 स्वतंत्र व्यावसायिक प्रभागों के गठन के प्रस्ताव पर सहमति प्रदान की गई। इसमें परिसंपत्ति प्रबंधन और पीपीपी मोड, सूचना प्रौद्योगिकी, शहरी गतिशीलता और नमामि नर्मदे तथा हरित एवं नदी संरक्षण के लिए प्रभागों का गठन प्रस्तावित है। परिसंपत्ति प्रबंधन और पीपीपी प्रभाग के अंतर्गत नगरीय निकायों को आत्मनिर्भर बनाने, जन हित कार्यों में निजी निवेश को प्रोत्साहित करने, वित्तीय अनुशासन, नीति आयोग तथा अन्य संबद्ध विभागों से समन्वय तथा मेट्रोपोलिटन एरिया डेवलपमेंट प्लानिंग को प्राथमिकता से लिया जाएगा। इसमें सोलर प्रोजेक्ट्स, हरित बांड, अप्रयुक्त परिसंपत्तियों के वैकल्पिक उपयोग जैसे नवाचार भी प्रस्तावित हैं। सूचना प्रौद्योगिकी प्रभाग के अंतर्गत ई-नगर पालिका प्रणाली, सीसीटीवी-जीआईएस आधारित निगरानी व्यवस्था, नागरिक सेवा प्लेटफार्म के उन्नयन, टोल संग्रह ई-पोर्टल एवं ऑनलाइन राजस्व संग्रहण जैसी स्मार्ट सिटी प्रणालियां संचालित की जाएंगी।

डिजिटल तरीके से होगी जनगणना, अप्रैल से शुरू होगा पहला चरण

आगामी जनगणना की तैयारियों को लेकर डीसी ने ली अधिकारियों की बैठक

एसबी ब्यूरो प्रमुख/निर्मल कुमार

कैथल। राष्ट्रीय जनगणना को लेकर प्रशासनिक स्तर पर हलचल तेज हो गई है। मंगलवार को लघु सचिवालय स्थित सभागार में डीसी अपराजिता की अध्यक्षता में हुई बैठक में जनगणना के सफल और सटीक संचालन के लिए विस्तृत रणनीति तैयार की गई। डीसी ने बताया कि इस बार जनगणना पूरी तरह ऑनलाइन और ऐप आधारित होगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि वे निर्धारित गाइडलाइन का पालन करते हुए इस राष्ट्रीय कार्य को सफल बनाएं। डेटा की गोपनीयता सुनिश्चित की जाए।

डीसी अपराजिता ने कहा कि यह प्रक्रिया मुख्य रूप से दो चरणों में विभाजित की गई है। प्रथम चरण अप्रैल 2026 में प्रस्तावित है, इसमें मुख्य रूप से मकानों की सूची तैयार की जाएगी और नागरिक रजिस्टर को अपडेट करने का कार्य किया जाएगा। वहीं दूसरा चरण फरवरी-मार्च 2027 में शुरू होगा। इस मुख्य चरण में जनसंख्या की गणना होगी। खास बात यह है कि इस बार सेल्फ-इन्यूमरेशन का विकल्प भी मिलेगा, यानी नागरिक स्वयं ऐप या पोर्टल के माध्यम से अपनी जानकारी दर्ज कर सकेंगे।

बैठक में बताया गया कि तकनीक का उपयोग इस प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी, कुशल और त्वरित बनाएगा। इससे डेटा प्रोसेसिंग में लगने वाला समय काफी कम हो जाएगा। जनगणना कार्य में शामिल सभी कर्मचारियों को मोबाइल ऐप और डिजिटल पोर्टल के उपयोग के लिए गहन प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित अधिकारी तैयारी शुरू करें। इस कार्य के लिए विभिन्न विभागों का सहयोग जरूरी है। इसमें प्रगणक और पर्यवेक्षक लगाए जाएंगे। इस कार्य के लिए शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लिए कुल 10 चार्ज ऑफिसर लगाए जाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित तहसीलदार तथा शहरी क्षेत्र में नगर परिषद या नगर पालिका के सचिव चार्ज ऑफिसर के रूप में कार्य करेंगे।

डीसी अपराजिता ने कहा कि उद्देश्य नागरिकों को यह समझाना है कि जनगणना केवल आंकड़े एकत्रित करना नहीं है, बल्कि भविष्य की सरकारी योजनाओं और विकास का आधार है। इसमें हर व्यक्ति की सहभागिता आवश्यक है, क्योंकि जनगणना का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि एक भी व्यक्ति छूटे नहीं।

इस अवसर पर डिवीजन सेंसेस इंचार्ज रामदासो, डीएमसी कपिल शर्मा, गुहला एसडीएम कैप्टन प्रमेश सिंह, सीटीएम गुरविंद्र सिंह, डीआरओ चंद्रमोहन, डीआईओ दीपक खुराना, डीआईपीआरओ नसीब सैनी, जिला सांख्यिकी अधिकारी निर्मल देवी, जिला समन्वयक अधिकारी ज्योति राणा सहित अन्य विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

बायो मेडिकल वेस्ट का सुनियोजित और नियमानुसार प्रबंधन करें सुनिश्चितः उप मुख्यमंत्री शुक्ल

एसबी संवाददाता

भोपाल। उप मुख्यमंत्री राजेन्द्र शुक्ल ने मंत्रालय, भोपाल में लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के विभिन्न विषयों की विस्तृत समीक्षा की। प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने, चिकित्सा अधोसंरचना के विस्तार से जुड़े प्रस्तावों पर चर्चा कर उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने रीवा, सिंगरौली, ग्वालियर, सागर एवं बुधनी मेडिकल कॉलेजों के निर्माण कार्यों की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने निर्माण कार्यों को निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्ता से पूर्ण करने के निर्देश दिए। साथ ही, आवश्यक उपकरणों की उपलब्धता, मानव संसाधन की नियुक्ति और शैक्षणिक एवं चिकित्सकीय गतिविधियों के सुचारु संचालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया।

उप मुख्यमंत्री शुक्ल ने बायो मेडिकल वेस्ट के वैज्ञानिक एवं सुनियोजित प्रबंधन सुनिश्चित के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि सभी स्वास्थ्य संस्थानों में बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाये, पृथक्करण, संग्रहण, परिवहन एवं निस्तारण की व्यवस्था को प्रभावी बनाने और पर्यावरण संरक्षण के मानकों का पालन करने के निर्देश दिए।

बैठक में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (पीएचसी), सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) और जिला चिकित्सालयों के उन्नयन से संबंधित प्रस्तावों की भी समीक्षा की गई। उप मुख्यमंत्री श्री शुक्ल ने कहा कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की सुलभता और गुणवत्ता में सुधार शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने उन्नयन प्रस्तावों को व्यावहारिक आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने और समयबद्ध क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक 9 जनवरी को: डीसी अपराजिता

संजना भारती संवाददाता

कैथल। डीसी अपराजिता ने बताया कि आगामी 9 जनवरी को दोपहर 12:15 आरकेएसडी कॉलेज के सभागार में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक का आयोजन होगा। इस बैठक की अध्यक्षता हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन एवं श्रम मंत्री अनिल विज करेंगे।

उन्होंने जिला के सभी विभागाध्यक्षों को निर्देश जारी करते हुए कहा कि सभी अधिकारी निर्धारित स्थान व समय पर पहुंचना सुनिश्चित करें।

शिक्षिका के सेवानिवृत्त होने पर विदाई समारोह आयोजित

संजना भारती संवाददाता

बछवाडा (बेगूसराय)। प्रखंड के राजकीय कृत गुरुसहाय मध्य विद्यालय रसीदपुर में विद्यालय प्रधानाध्यापक धवल किशोर की देखरेख में विदाई सह सम्मान समारोह आयोजित कर विद्यालय की शिक्षिका गिरीश कुमारी को सेवानिवृत्ति उपरांत उन्हें भावभीनी विदाई दी गयी।

इस अवसर पर विदाई समारोह में प्रधानाध्यापक धवल किशोर ने कहा कि शिक्षक कभी सेवानिवृत्त नहीं होते हैं। उच्च माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य राकेश कुमार ने कहा कि हम सभी शिक्षिक इनके दिखाये गये मार्गों का अनुसरण कर शिक्षा के क्षेत्र में अपनी अभूतपूर्व भूमिका निभाएंगें। कार्यक्रम की संचालन शिक्षिका सोनम कुमारी के द्वारा किया गया।

मौके पर राजेश सिंह यादव,जितेंद्र कुमार यादव, विवेक कुमार दुबे, दिवाकर मणि,सचिन कुमार कसौधन, गौतम कुमार राय,बबलू कुमार दास, कुमार न्यूटन, वीरेंद्र कुमार, रिंटू कुमारी, इशरत परवीन, नीलमणि कुमारी, ममता कुमारी, सोनम कुमारी, स्मृति किरण,अंजली कुमारी, रीना सिंह, रूही सुल्ताना, स्नेहा भारती, रम भारती, दीपिका रमन सहित कई अन्य कर्मी भी संबोधित कर विद्यालय से सेवानिवृत्त हो रहे शिक्षिका गिरीश कुमारी के प्रति अपना हृदय उदगार व्यक्त किया।

श्री हिंदू तख्त के तत्वावधान में एक भव्य एवं ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया

संजना भारती संवाददाता

मोहाली। श्री हिंदू तख्त के तत्वावधान में एक भव्य एवं ऐतिहासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता श्री हिंदू तख्त के महंत श्री प्रवीण कुमार (अध्यक्ष) ने की। इस अवसर पर पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, जम्मू-कश्मीर सहित विभिन्न राज्यों से पहुंचे साधु-संतों एवं पदाधिकारियों की गरिमामयी उपस्थिति रही। बैठक का शुभारंभ वैदिक मंत्रोच्चार एवं विधिवत पूजा-अर्चना के साथ किया गया, जिससे पूरे वातावरण में आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार हुआ।

बैठक के दौरान श्री हिंदू तख्त के विस्तार, सामाजिक दायित्वों और संगठन को और अधिक मजबूत करने को लेकर व्यापक विचार-विमर्श किया गया। विशेष रूप से जम्मू-कश्मीर से आए वरिष्ठ पदाधिकारियों ने वहां संगठन की बढ़ती सक्रियता और जनसमर्थन की जानकारी साझा की। उन्होंने बताया कि जम्मू-कश्मीर में श्री हिंदू तख्त का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है और संगठन का डंका

जोर-शोर से बज रहा है।

संगठन द्वारा समाजसेवा के क्षेत्र में किए जा रहे कार्यों की भी विस्तार से चर्चा हुई। बेटियों की शादी जैसे संवेदनशील और महत्वपूर्ण सामाजिक विषय पर श्री हिंदू तख्त द्वारा सराहनीय पहल की गई, जिसमें जम्मू-कश्मीर के पदाधिकारियों के सहयोग से जरूरतमंद परिवारों की बेटियों का विवाह संपन्न कराया गया। इस कदम की उपस्थित संत-समाज एवं पदाधिकारियों ने खुले दिल से सराहना की।

महंत श्री प्रवीण कुमार के सशक्त नेतृत्व में जम्मू-कश्मीर में युवाओं को संगठन से जोड़ते हुए उन्हें विभिन्न जिम्मेदारियां सौंपी गईं, जिससे वहां का युवा वर्ग राष्ट्र, धर्म और समाज सेवा के प्रति जागरूक हो रहा है। यह स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है कि श्री हिंदू तख्त जम्मू-कश्मीर में सबसे तेजी से विस्तार करने वाला संगठन बनकर उभरा है।

बैठक में यह भी बताया गया कि अब कनाडा में भी श्री हिंदू तख्त का प्रभाव तेजी से बढ़ रहा है। वहां के प्रवासी भारतीय और स्थानीय निवासी संगठन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। कनाडा में श्री हिंदू तख्त के प्रचार ने एक नया मोड़ लिया है और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर संगठन की पहचान मजबूत हो रही है।

हरियाणा, पंजाब, जम्मू-कश्मीर और कनाडा में फैलती श्री हिंदू तख्त की लहर इस बात का प्रमाण है कि संगठन समाज सेवा, धर्म रक्षा और राष्ट्रहित के अपने संकल्प पर मजबूती से आगे बढ़ रहा है। बैठक के अंत में संगठन की ओर से कई महत्वपूर्ण और दूरगामी फैसले लिए गए, जो आने वाले समय में श्री हिंदू तख्त को और अधिक सशक्त बनाएंगे।

कैजुअल हो या फॉर्मल लुक विंटर सीजन में आजमाएं

जैकेट्स के न्यू ट्रेंड

सर्दियों का फैशन यानी जैकेट्स और वुलेन्स का फैशन. इस मौसम की शुरूआत के साथ ही बाजार तमाम तरह की जैकेट्स और वुलेन्स से भर चुका है. ऐसे में जैकेट खरीदने से पहले इस सीजन के नए चलन की जानकारी हो जाए तो आपकी जैकेट जरूरत के साथ-साथ फैशन के पैमाने पर भी फिट बैठेगी.

लेदर जैकेट्स

सालों से लेदर जैकेट्स चलन में है और कभी आउटडेट नहीं होती हैं. हालांकि पुरुषों की अपेक्षा महिलाओं में इनका चलन आजकल अधिक है. लेदर जैकेट्स दिखने में जितनी डीसेंट हैं, बूट्स के साथ इनका कांबिनेशन उतना ही स्टाइलिश है. प्योर लेदर जैकेट और जीन्स का कांबिनेशन परफेक्ट कैजुअल लुक है. कैजुअल या फॉर्मल लुक के लिए आप स्वेट लेदर जैकेट भी चुन सकते हैं.

डेनिम जैकेट्स

सिंपल, स्टाइलिश और रफ एंड टफ लुक के लिए डेनिम जैकेट से अच्छा क्या ऑप्शन्स हो सकता है. डेनिम में ब्लू, ब्लैक और ऑफ व्हाइट शेड्स आप ट्राइ कर सकते हैं. लड़कियां डेनिम जैकेट्स के साथ चेरी, ब्राउन, पिंक, ग्रीन आदि रंगों का कांबिनेशन ट्राइ कर सकती हैं.

बॉम्बर जैकेट्स

इस सीजन में बॉम्बर जैकेट्स वापस चलन में हैं। ये सिर्फ स्मार्ट ही नहीं लगती बल्कि आरामदायक भी हैं. साथ ही, बहुत अधिक ठंड में आराम से पहना जा सकता है। ब्लैक, ब्लू व अलग-अलग रंगों के कांबिनेशन में भी इन्हें ट्राइ कर सकते हैं.

शेल जैकेट

शेल जैकेट सर्दियों के लिए परफेक्ट जैकेट है. यह आपको स्पोर्टी लुक देगी. ब्लू डेनिम जीन्स के साथ इसका कांबिनेशन बेहद स्मार्ट है. चूंकि इसमें आप जिप को गले तक चढ़ाकर खुद को पूरी तरह कवर कर सकते हैं इसलिए आप ट्रैवलिंग के दौरान बेझिझक होकर इसे ट्राइ करें.

कॉट्रॉय जैकेट

सेमी फॉर्मल और कैजुअल लुक के लिए कॉटरॉय जैकेट्स भी बेहतरीन ऑप्शन्स हैं. इनमें ऑफ व्हाइट, ब्राउन, चेरी, ब्लैक आदि कलर काफी चलन में हैं. आप इन्हें फॉर्मल ट्राउजर के साथ पहनकर सेमी फॉर्मल लुक दे सकते हैं जबकि जीन्स के साथ यह पूरी तरह से कैजुअल लगती हैं.

गाज़र का जूस चेहरे पर लाता है चमक

रक्त की विषाक्तता करता है कम

गाजर ऐसा खास फल है जो सलाज, हलवा, सब्जी, जूस आदि कई तरीके से खाया जा सकता है। इसी तरह खास इसके गुण भी हैं क्योंकि इसके खाने के कई लाभ हैं।

गाजर खाने के फायदे

रोजाना गाजर का सलाद खाने से या गाज़र का जूस पीने से चेहरे पर चमक आती है। गाजर रक्त की विषाक्ता कम करता है और इसके सेवन से कील-मुहासों से भी छुटकारा मिलता है।

गाजर में विटामिन 'ए' अधिक मात्रा में पाया जाता है. इसलिए अगर गाजर का नियमित रूप से सेवन किया जाए तो आंखों की रोशनी बढ़ सकती है।

» गाजर का जूस पीने से शरीर में हिमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ जाती हैं, और गाजर में अधिक मात्रा में फाइबर पाया जाता हैं जो शरीर की पाचनशक्ति को बढ़ाता हैं।

» गाजर में कैरोटीनायड होता है, जो हृदय रोगियों के लिए अच्छा होता है। यह माना जाता है कि गाजर का प्रतिदिन सेवन कालेस्ट्राल के स्तर को कम करता है।

» गाज़र के प्रतिदिन सेवन से रक्त में शर्करा का स्तर ठीक रहता है।

» इसे खाने से मसूड़ों से ब्लड आना बंद हो जाता है और दांतों की चमक बढ़ती है।

» गाजर में बीटा कैरोटीन होती है और यह प्रतिरक्षा प्रणाली के लिए अच्छा होता है। गाजर के रस में मिश्री व काली मिर्च मिलाकर पीने से खाँसी ठीक हो जाती है तथा कफ कि समस्या में भी आराम मिलता है। गाज़र खाने से, पेट और फेफड़ों के कैंसर का जोखिम कम होता है।

जिंदगी में एक बार जरूर जाएं

भूटान, ये रही 6 वजहें...

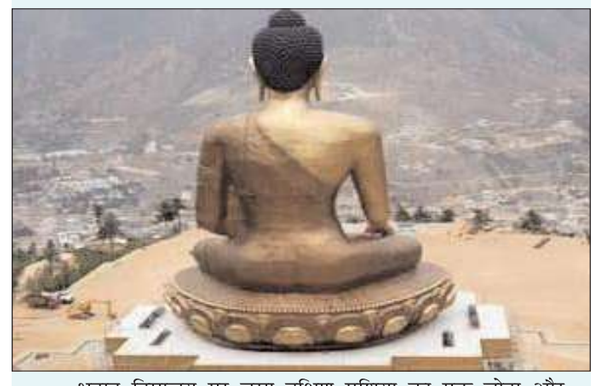

भूटान हिमालय पर बसा दक्षिण एशिया का एक छोटा और महत्वपूर्ण देश है. यह देश चीन (तिब्बत) और भारत के बीच स्थित है. सैलानियों के बीच भूटान अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है. प्राकृतिक सौंदर्य से भरपूर ये देश सैलानियों को कई रहस्यमयी चीजों से रूबरू कराता है. जानिए भूटान के बारे में ऐसी 6 बातें जो आपको यहां आने पर मजबूर कर देंगी...

टाइगर नेस्ट मोनास्ट्री

टाइगर नेस्ट मोनास्ट्री भूटान के प्रमुख पर्यटन स्थलों में से एक हैं. कई सौ साल पुरानी इस मोनास्ट्री का निर्माण 1692 में हुआ था. कहते हैं गुरु पद्मासम्भवा यहां तीन साल, तीन महीने, तीन हफ्ते, तीन दिन और तीन घंटों तक ध्यान में लीन थे.

बुद्ध प्रतिमा

ग्रेट बुद्ध डोरडेन्मा शाक्यमुनि बुद्ध प्रतिमा है, जोकि विश्व में बुद्ध की कुछ एक सबसे ऊंची प्रतिमाओं में से एक है. इसकी ऊंचाई करीब 169 फीट (51.5 meters) है.

अनोखा कल्चर

भूटान अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं के लिए जाना जाता है. यहां का चम डांस काफी लोकप्रिय है.

खूबसूरत पहाड़ और वादियां

भूटान में ट्रेकिंग का अपना ही अलग मजा है. यहां हिमालय के पहाड़ों में ट्रेकिंग करना किसी एडवेंचर से कम नहीं है. अगर आपको ट्रेकिंग का मजा लेना है तो इसके लिए आपको अप्रैल के मौसम में जाना चाहिए. वहीं अगर मौसम का लुत्फ उठाना है तो इसके लिए आपको अक्टूबर के महीने में जाना चाहिए.

आर्कीटेक्चर

भूटान में एक से बड़ कर एक किले और मोनास्ट्रियां हैं. यहां की खूबसूरत इमारतें पर्यटकों के दिलों को छू लेने वाली हैं.

खानपान

यहां का खान पान भी और जगहों से बिलकुल अलग है. यहां के खाने को स्वादिष्ट बनाने के लिए हैंडमेड चीज, ड्राइड एगप्लांट, याक बटर और बीटल लीव्स जैसी स्थानीय सामग्रियों का इस्तेमाल किया जाता है.

ठंड में बढ़ा लें विटामिन डी की मात्रा, करें नींबू का सेवन

ठंड में आपको शरीर संबंधी कई समस्याएं शुरू होंगी। डॉ. कृष्णा सिंह बताती है कि इससे बचने के लिए विटामिन डी की मात्रा अधिक लेनी चाहिए।

इसके लिए जरूरी है कि हर दिन 4-5 नींबू खाने में ले।

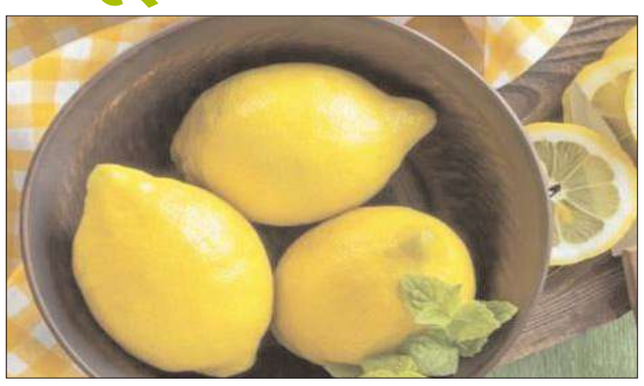

नींबू के फायदे

» नींबू में विटामिन की कई ऐसी मात्राएं पायी जाती है जो मांसपेशी के दर्द से निजात दिलाता है।

» ठंड में दांत और मसूड़े में भी समस्या बढ़ती है। नींबू के इस्तेमाल से इससे फायदा पहुंचता है।

» गठिया बीमारी ठंड के मौसम में बढ़ जाती है। इसमें नींबू बेहतर काम करता है।

» नींबू के इस्तेमाल से सांस संबंधी परेशानी भी दूर हो जाती है।

» गैस, कब्ज, भूख न लगना और त्वचा संबंधी परेशानी ठंड में बढ़ती है। ऐसे में नींबू की पूरी मात्रा लेने से काफी राहत मिलती है।

रोज लें पालक का जूस, बीमारियों से रहेंगे दूर

पालक की पत्तियों में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसमें मिनरल्स, विटामिन और दूसरे कई न्यूट्रीएंट्स भरपूर मात्रा में पाए जाते है। अगर पालक का पूरा फायदा चाहिए तो पालक का जूस पीना सबसे ज्यादा फायदेमंद होता है। पालक के जूस में विटामिन ए, सी, ई, के और बी कॉम्प्लेक्स अच्छी मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा इसमें मैगनीज, कैरोटीन, आयरन, आयोडीन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटैशियम, सोडियम, फॉस्फोरस और आवश्यक अमीनो एसिड भी पाए जाते हैं।

ये हैं वो कारण जिसकी वजह से दी जाती है पालक का जूस पीने की सलाह

पालक में मौजूद कैरोटीन और क्लोरोफिल कैंसर से बचाव में सहायक हैं। इसके अलावा ये आंखों की रोशनी के लिए भी अच्छा है। पाचन क्रिया को दुरुस्त रखने के लिए भी पालक का जूस पीने की सलाह दी जाती है।

ये शरीर के विषाक्त पदार्थों को बाहर निकालने में मददगार है. इसके अलावा अगर आपको कब्ज की समस्या है तो भी पालक का जूस आपके लिए फायदेमंद रहेगा।

पालक में विटामिन के की अच्छी मात्रा होती है. ऐसे में पालक का जूस पीने से हड्डियां मजबूत होती हैं।

अगर आपको त्वचा से जुड़ी कोई समस्या है तो पालक का जूस पीना आपके लिए फायदेमंद रहेगा. पालक का जूस पीने से त्वचा निखरी और जवान बनी रहती है.ये बालों के लिए भी अच्छा है।

गर्भवती महिलाओं को भी पालक का जूस पीने की सलाह दी जाती है. पालक का जूस पीने से गर्भवती महिला के शरीर में आयरन की कमी नहीं होती है.

प्रेग्नेंसी में बचे इस बात से, वरना मुश्किल में आ सकती हैं आप

पेग्नेंसी में कुछ बातों को नजर अंदाज करना आप और आपके शिशु के लिए घातक हो सकता है. लंदन में हुए एक शोध में यह दावा किया गया है, इसमें सबसे घातक प्रेग्नेंसी में तनाव की समस्या है. इस दौरान यदि मां किसी प्रकार से भी तनाव में हो तो गर्भपात के खतरे बढ़ जाते हैं.

प्रेग्नेंसी हर महिला के जीवन का सबसे संवेदनशील वक्त होता है. ये ऐसा समय होता है जब उन्हें कई तरह की सावधानियां बरतनी पड़ती हैं, जिससे न सिर्फ उनका स्वास्थ्य बेहतर बना रहे बल्कि उनके बच्चे की सेहत पर भी कोई प्रतिकूल असर न पड़े. ऐसे में उन्हें अपनी डाइट के साथ अपनी आदतों में भी बदलाव लाने पड़ते हैं. प्रेग्नेंसी के दौरान हर महिला को कोई भी भारी या रिस्की काम करने की मनाही होती है. इसके साथ उन्हें

चिंता करने या फिर तनाव में रहने के लिए भी मना किया जाता है. गर्भावस्था में महिला का तनाव में रहना गर्भपात का खतरा बढ़ा देता है. शोध तनाव ग्रस्त और तनाव रहित महिलाओं को लेकर किया गया.

शोध में कहा गया जिन महिलाओं ने इस दौरान तनाव लिया उनके साथ गर्भपात की संभावना कई फीसदी तक बढ़ गई. चीन में हुए एक अन्य शोध में भी इस बात का पता चला है कि प्रेग्नेंसी के दौरान तनाव लेने वाली महिलाओं में गर्भपात का खतरा तकरीबन 42 फीसदी तक बढ़ जाता है. शोध के मुताबिक प्रेग्नेंट महिलाओं को सजग हो जाने की जरूरत है.

आपको ये करना होगा...

प्रेगनेंट महिला को चाहिए कि प्रेग्नेंसी के दौरान वह ज्यादा से ज्यादा खुश रहने की कोशिश करें. तनाव से दूर रहने की कोशिश करें. किसी भी तरह के घरेलू काम से छुट्टी लेकर ज्यादा से ज्यादा आराम करें. तनाव से दूरी बनाने के लिए योग का सहारा लें. शरीर को पर्याप्त मात्रा में पोषक तत्व देने वाले आहार का सेवन करें ताकि शरीर ऊर्जा से भरपूर रहे. अधिक से अधिक पानी का सेवन करें, उन फलों (संतरा, मौसम्बी) का सेवन करें, जो तत्काल दिमाग को रिलैक्स करने में मदद करते हैं. इसके बाद भी अगर किसी तरह की समस्या है तो तुरंत डॉक्टर को दिखाएं.

रेसिपी

कॉफी नानखताई

सामग्री

चीनी पाऊडर 170 ग्राम,घी 120 ग्राम,मैदा 145 ग्राम

बेसन 30 ग्राम,बेकिंग पाऊडर 2 चम्मच,सूजी 2 चम्मच,इलायची पाऊडर 2 चम्मच

इंस्टेंट कॉफ़ी डेढ़ चम्मच,इंस्टेंट कॉफ़ी गार्निशिंग के लिए,चीनी गार्निशिंग के लिए।

विधि

एक बाउल में 170 ग्राम पाऊडर चीनी पाऊडर, 120 ग्राम घी डालकर इसे अच्छी तरह से फेंट लें। अब इसके ऊपर एक छन्नी में 145 ग्राम मैदा, 30 ग्राम बेसन, 2 चम्मच बेकिंग पाऊडर, 2 चम्मच सूजी डालकर छान लें। इसमें 2 चम्मच इलायची पाऊडर, डेढ़ चम्मच इंस्टेंट कॉफी डालकर अच्छी तरह से मिक्स करें। फिर इसे नर्म आटे की तरह गूंथ लें। इसे 15 मिनट के लिए फीज में रखे दें। अब इस मिश्रण की 15-16 छोटी-छोटी गेंदें बना लें। इसके बाद इस पर थोड़ी सी इंस्टेंट कॉफी और चीनी डालें। ओवन को 3350एस/180एष्ट पर प्रीहीट करें। फिर तैयार की गई गेंदों को 15 से 20 मिनट के लिए बेक करें। आपके कॉफी नानखताई तैयार हैं। इसे सर्व करें।

पाइनेप्पल क्रश डिलाइट

सामग्री

230 ग्राम- चीनी, 1 टेबलस्पून- पानी

225 ग्राम- फ्रेश क्रीम

40 ग्राम- पीसी चीनी

1/4 टीस्पून- वनिला एसेंस,फ्रुट केक

पाइनेपल सिरप अनानास

विधि

सबसे पहले एक पैन में चीनी और एक टेबलस्पून पानी डालकर इसे मध्यम आंच पर गर्म करें। अब बटर पेपर पर पिघली हुई चीनी को डाल कर 5-10 मिनट के लिए रख दें ताकि यह सूख जाए। इसके बाद एक बाउल में फ्रैश क्रीम,चीनी और वनिला एसेंस डालकर मिक्स कर लें। अब एक पैरेक्स डिश (कांच के बर्तन) में फ्रूट केक की एक तह बिछा दें और इसके ऊपर पाइनेप्पल सिरप डालें। सिरप डालने के बाद इसके ऊपर अनानास के कटे हुए टुकडे रखें और पहले से तैयार की हुई क्रीम को इसके डालें। क्रीम को एकसार करें। इसे क्रश चीनी के साथ गार्निश करके 30 मिनट फ्रीजर में रखें और सर्व करें।

हरी धनिया के इस्तेमाल से मिलेगी कई बीमारियों से राहत

हरी धनिया आपकी कई तरह की बीमारियां खत्म हो सकती है। अपने इन्हीं गुणों के कारण इसका महत्त्व और भी ज्यादा बढ़ जाता हैं। इसके पानी में कैल्शियम, पोटैशियम, विटामिन सी इत्यादि मौजूद होते हैं तो आइए जानते हैं इसके फायदों के बारे में।

वजन कम करें

अगर आप अपना वजन कम करना चाहती हैं तो तीन बड़े चम्मच धनिए के बीज को एक ग्लास पानी में उबाल लें। जब पानी आधे से कम हो जाएं तो इसे छान लें। इस पानी को प्रतिदिन दो बार सेवन करने से आपका वजन कुछ ही दिनों में कम हो जाएगा।

पिंपल्स से छुटकारा

पिंपल्स की समस्या से छुटकारा पाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता हैं। इसे इस्तेमाल करने के लिए धनिए के जूस में हल्दी पाउडर मिलाएं और अपने चेहरे पर लगाएं। फिर कुछ देर बाद चेहरे को पानी से धो लें। इस लेप को दिन में दो बार इस्तेमाल करें। इससे पिंपल्स से छुटकारा मिलेगा और आपके चेहरे की सुंदरता भी बढ़ेगी।

आँखों की परेशानियों से राहत

आँखों में दर्द, पानी गिरना, जलन आदि की समस्या में इसके इस्तेमाल से तुरंत राहत मिलती हैं। इसके लिए आप थोड़ा सा धनिया लेकर पीस लें फिर उसे पानी में डालकर उबाल लें। थोड़ी देर उबलने के बाद इसे ठंडा करें और छान कर किसी बर्तन में रख लें। प्रतिदिन इनकी दो दो बूँद आँखों में डालने से आँखों की समस्या से राहत मिलती हैं।

पीपल सेहत भी सुधारता है, जानिए इसके गुण

भारतीय संस्कृति में पीपल वर्षों से पवित्र पेड़ के रूप में पूजा जाता रहा है। वहीं इसे अपनी घनी छांव और ताजा प्राणवायु के लिए जाना जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पीपल का पेड़ आपको सेहत से जुड़े लाभ भी देता है? जानते हैं कुछ ऐसे ही लाभ के बारे में। इस बात का जिक्र वेदों में भी मिलता है। पीपल के इन चमत्कारी गुणों में से हम यहां ऐसे ही कुछ गुणों की बातें कर रहे हैं।

1 सांस की तकलीफ : सांस संबंधी किसी भी प्रकार की समस्या में पीपल का पेड़ आपके लिए बहुत फायदेमंद हो सकता है। इसके लिए पीपल के पेड़ की छाल का अंदरूनी हिस्सा निकालकर सुखा लें। सूखे हुए इस भाग का चूर्ण बनाकर खाने से सांस संबंधी सभी समस्याएं दूर हो जाती है। इसके अलावा इसके पत्तों का दूध में उबालकर पीने से भी दमा में लाभ होता है।

2 गैस या कब्ज : पीपल के पत्तों का प्रयोग कब्ज या गैस की समस्या में दवा के तौर पर किया जाता है। इसे पित्त नाशक भी माना जाता है, इसलिए पेट की समस्याओं में इसका प्रयोग लाभप्रद होता है। इसके ताजे पत्तों के रस निकालकर सुबह शाम एक चम्मच पीने से पित्त के साथ ही समस्याएं भी समाप्त होती हैं।

3 दांतों के लिए : पीपल की दातुन करने से दांत मजबूत होते हैं, और दांतों में दर्द की समस्या समाप्त हो जाती है। इसके अलावा 10 ग्राम पीपल की छाल, कत्था और 2 ग्राम काली मिर्च को बारीक पीसकर बनाए गए मंजन का प्रयोग करने से भी दांतों की सभी समस्याएं समाप्त हो जाती हैं।

4 विष का प्रभाव : किसी जहरीले जीव-जंतु द्वारा काट लेने पर अगर समय पर कोई चिकित्सक मौजूद नहीं हो, जब पीपल के पत्ते का रस थोड़ी-थोड़ी देर में पिलाने पर विष का असर कम होने लगता है।